RNI NO. CHHHIN/17604 TC

लाईफ वर्सिटी

मासिक

वर्ष : 1 | अंक : 03 | माह : अगस्त, 2023 | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 5 रू.

NDA बनाम INDIA और मोदी का आत्मविश्वास

नरेन्द्र पाण्डेय

देश की महाअदालत यानि उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम को ले कर की गई टिप्पणी के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर 4 अगस्त, 2023 को रोक लगा दी. 2019 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी ने महाअदालत की ओर रुख किया था.

सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि मानहानि के मामले में देशभर में लाखों मामले आज भी चल रहे हैं और पहले भी चले होंगे मगर कभी भी किसी को इतनी कठोर सजा नहीं मिली होगी. सब से बड़ी बात यह है कि इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के चेहरे जहां पहले खिले हुए थे, अब मुरझाए दिखाई दिए. उच्चतम न्यायालय के फैसले का किसी भी बड़े नेता ने स्वागत नहीं किया है. आमतौर पर राजनीति को खेल भावना से लिया जाना चाहिए, देशसेवा की भावना से लिया जाना चाहिए. अगर आज भाजपा देश की सत्ता चला रही है और देश का विकास करने का प्रयास कर रही है तो कल कांग्रेस ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

भाजपा के खिलाफ 26 राजनीतिक दलों के जुटान के बाद विपक्षी दलों को इस गठबंधन को इं.डि.या. नाम देना राष्ट्रवाद पर भाजपा के एकाधिकार को चुनौती देने की सोचीसमझी रणनीति है. इस में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो' यात्रा का मूल संदेश भी शामिल है, जो देश के सभी समुदायों, जातियों और अलगअलग संस्कृतियों के बीच भाईचारा मजबूत कर के भारत की धर्मनिरपेक्षता व अखंडता को बचाए रखने की कोशिशों पर आधारित है. यह पहली बार नहीं है कि अनेक राजनीतिक दलों ने एक मंच पर आ कर सत्ता में बैठी पार्टी को ललकारा है. आज वह वक्त भी याद करने की जरूरत है जब इस से पहले भी कई बार देश ने विपक्षी एकजुटता देखी और सरकारें बदलती देखीं.

याद करें जब 1977 में पहली बार विपक्षी नेता साथ आए तो सत्ता उलट गई और गठबंधन की सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाली. देश में इमरजैंसी के बाद पहली बार 1977 में विपक्षी नेता एकसाथ आए थे. तब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैरकांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था.

इसके बाद 1989 में जनता पार्टी ने अलग-अलग दलों के समर्थन से वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई थी. फिर एनडीए ने 1996 में भाजपा ने अटल बिहारी बाजपेयी को चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ा और भाजपा सब से बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने छोटेछोटे दलों के साथ मिल कर बिना प्रधानमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ा और जीता था, तब यूपीए में कांग्रेस के नेता के रूप में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे. 2009 में फिर मुकाबला एनडीए बनाम यूपीए में हुआ. यह वह समय था जब राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह 2 खेमों, यूपीए और एनडीए में बंट गई थीं. उस चुनाव में भी यूपीए की जीत हुई.

उधर 38 पार्टियों वाली एनडीए ने दिल्ली में 2024 की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है. अगला लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया होगा. एनडीए पर मंथन इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इस बार 2019 को दोहरा पाना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा. भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार होगा जब इतनी सारी पार्टियों से मिल कर बने 2 गठबंधन आपस में भिड़ेंगे.

नरेंद्र मोदी की अगुआई में एनडीए को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भारी जीत मिली. उस सिलसिले को बरकरार रखने और जीत की हैट्रिक बनाने की चुनौती अब मोदी और शाह के सामने है. 2019 में विपक्ष उस तरह से एकजुट नहीं था, जिस की तैयारी इस बार चल रही है. उस के साथ ही जिस तरह से 2019 में भाजपा मजबूत दिख रही थी, वैसी मजबूत स्थिति में वह इस बार नहीं है.

लाल किले की प्राचीर से 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने 2014 में बदलाव लाने का वादा किया था। उन्होंने कहा, ''आपने मुझ पर भरोसा जताया। आपने मुझ पर जो भरोसा जताया था, मैंने उसे पूरा करने की कोशिश की। इससे पिछले पांच वर्षों में मुझे आत्मविश्वास मिला है। मैंने आपसे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए बदलाव लाने का वादा किया था। मैंने राष्ट्र के लिए कड़ी मेहनत की है और मैंने इसी भावना के साथ काम किया है।''

भारत पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र, दूसरे देशों को सीखने की जरूरत: डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डॉ. टेड्रॉस अदनॉम गैब्रेयसस ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारत इसका केंद्र रहा है। करीब 3500 साल से इस चिकित्सा का लाभ लिया जा रहा है। आज भी करीब 40 फीसदी दवाओं और फार्मास्युटिकल उत्पादों का आधार प्राकृतिक उत्पाद हैं। अन्य देशों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।

गुजरात के गांधीनगर में बृहस्पतिवार को शुरू हुए पारंपरिक चिकित्सा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में डॉ. गैब्रेयसस ने कहा कि भारत ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा की ताकत बढ़ाने के लिए काफी बेहतर कार्य किए हैं। इन कार्यों को अपनाकर अन्य देशों को भी पारंपरिक चिकित्सा को आगे लाने का काम करना चाहिए। उन्होंने भारत सहित उन देशों से साक्ष्य आधारित कार्यों को लेकर सुझाव मांगे हैं, जहां पारंपरिक चिकित्सा पर सबसे ज्यादा कार्य किया जा रहा है। बाद में डब्ल्यूएचओ इन सुझावों को वैश्विक रणनीति में शामिल कर सकता है। उद्घाटन सत्र में डॉ. गैब्रेयसस ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन में लिए गए फैसले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक दवाओं के उपयोग को एकीकृत करेगी। साथ ही विज्ञान के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा की शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी।पारंपरिक चिकित्सा में ये शामिल

केंद्रीय आयुष मंत्रालय इस सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है। पारंपरिक चिकित्सा में एक्यूपंक्चर, हर्बल दवाएं, स्वदेशी पारंपरिक चिकित्सा, होम्योपैथी, **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान अपनाएं : मनसुख मांडविया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को अपनाकर, हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य लोकाचार को बढ़ावा देते हुए स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आधुनिक समय में प्राकृतिक और हर्बल आधारित फार्मास्यूटिकल्स व सौंदर्य प्रसाधनों की मांग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के स्थायी महत्व को रेखांकित करती है

डॉ अनिल गुप्ता कर रहे है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ पर कार्य

रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉ अनिल गुप्ता ने वैदिक विज्ञान मे पी एच डी करने के पश्चात इंटेगरटेड होलिस्टिक हेल्थ पर कर रहे है अपकी संस्था पाज़िटिव हेल्थ ज़ोन मे आप अपने टीम के साथ अंतर्राष्टीय क्वांटम मशीनों द्वारा व्यक्ति का औरा, चक्रों का संतुलन,नाड़ियों मे लाइफ फोर्स एनर्जी के ब्लाकिज आदि का पता लगाने के साथ साथ त्रिदोष (वात,पित्त,और कफ) का अध्ययन कर आयुर्वेद,पंचकर्म ,योग ,ध्यान मुद्रा विज्ञान ,प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान ,एक्यूप्रेशर आदि के माध्यम से सम्पूर्ण स्वास्थ्य पर कार्य किया जा रहा है। डॉ अनिल का मानना है की भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और वैदिक विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर और प्रैक्टिकल बनाने के आवश्यकता है।

दिव्य काँवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई कांग्रेस नेता भी हुए सम्मिलित

बोल बम'' और ''हर हर महादेव'' के नारों से गूँज उठा पश्चिम विधानसभा सहित पूरा रायपुर शहर

रायपुर। संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के विधायक, श्री विकास उपाध्याय के नेतृत्व में 21 अगस्त को आयोजित दिव्य एवं विशाल काँवड़ यात्रा बहुत ही भक्तिमय, संगीतमय एवं आनंदमय रूप से सफल हुआ। दिव्य काँवड़ यात्रा गुढ़ियारी स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर, मारुति मंगलम भवन में धर्मगुरुओं के द्वारा किये जा रहे पूरे विधि विधान से भगवान शंकर जी एवं उनके काँवड़ की पूजा-अर्चना में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई कांग्रेस नेता भी सम्मिलित हुए तथा इस दौरान 50000 से भी ज्यादा श्रद्धालुगणों का जनसैलाब श्री शंकर भगवान जी की भक्ति में उमड़े।

विधायक विकास उपाध्याय अपने परिवार सहित स्वयं भी काँवड़ धारण किये एवं बोल बम व हर हर महादेव का उच्चारण कर इस दिव्य यात्रा का शुभारंभ किये। उनके साथ पूरे पश्चिम विधानसभा के निवासी एवं कई हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण भी काँवड़ लिये इस यात्रा में झूमते गाते निकल पड़े। विधायक विकास उपाध्याय के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों में पानी, शरबत, फल, नाश्ते एवं बाबा हटकेश्वर मंदिर महादेव घाट में समस्त श्रद्धालुओं के लिए भोजन की सुव्यवस्था भी की एवं श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य टीम द्वारा एम्बुलेंस व पुलिस सहायता केन्द्र व पुलिस बलों द्वारा पूर्ण सुरक्षा साथ ही वहाँ उपस्थित काफी संख्या में वालेंटियरों ने भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है एवं विभिन्न मुख्य चौंक-चौराहों के पास दिव्य काँवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ भव्य रूप से स्वागत अभिनंदन भी किया गया। जिस पर विधायक विकास उपाध्याय ने सभी का आभार व्यक्त किया है।

यह यात्रा गुढ़ियारी मारुति मंगल से गुढ़ियारी पड़ाव होते हुए शुक्रवारी बाजार, फिर पहाड़ी चौक होते हुए भारत माता चौक, फिर सीएसईबी के पास से होते हुए कर्मा माता चौक, उसके बाद कबीर चौक होते हुए फ्लाई ओवर चढ़कर तेलघानी नाका चौक, फिर अग्रसेन चौक होते हुए आजाद चौक थाना के सामने आमापारा होते हुए लाखेनगर वाले रास्ते से अश्वनी नगर, सुन्दर नगर चौक होते हुए रायपुरा चौक से सीधे महादेव घाट मार्ग होते हुए बाबा हटकेश्वर नाथ महादेव श्री शंकर भगवान जी के मंदिर में पहुँची। जहाँ विधायक विकास उपाध्याय एवं उनके परिवार व समस्त श्रद्धालुगणों ने काँवड़ में लिये जल को भगवान हटकेश्वर शिवलिंग में सहस्त्रधार सहित चढ़ाकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किये। वहीं विधायक विकास उपाध्याय ने प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।

औरा,चक्रों और नाड़ी परीक्षण हुआ आसान

पाजीटिव हेल्थ जोन दुर्ग में भी देगा बीमारियों का सम्पूर्ण समाधान

दुर्ग। वर्तमान की भाग दौड़ और डीजिटेलाइजेशन की दुनियाँ में लोगों का शाररिक श्रम कम एवं मानसिक क्रियाशीलता बढ़ गई है जिससे स्ट्रेस ,डिप्रेशन, एंजाईटी और विभिन्न प्रकार की सायकोसोमेटिक बीमारियाँ लोगों को परेशान कर रही हैं।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ अब सभी चिकित्सा पद्धतियाँ इस बात पर एक मत है की मानव शरीर में होने वाली 85 प्रतिशत बिमारियों का एक कारण मनोविकार है। उक्त महामारी से समस्त मानव जाती को बचाने में योग एक कारगर उपाय है क्योंकि योग का सूत्र ही है **'मन चित्त निरोधः'** भगवद गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है - **असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥** अर्थात किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए. क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं. इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें.

उक्त बाते दुर्ग में पाजीटिव हेल्थ जोन के नए ब्रांच के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि की आसंदी से छग योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा ने कही। सेंटर का अवलोकन करने के पश्चात ज्ञानेश जी ने कहा की की यहाँ उपलब्ध मशीने हमारे आयुर्वेद और वैदिक चिकित्सकीय की प्रमाणिकता को तथ्यात्मक रूप दे रहा है।

ज्ञात हो की छग के प्रसिद्द नेत्र रोग विशेषग्य,श्रीगणेश विनायक हॉस्पिटल,रायपुर के डायरेक्टर एवं पाजीटिव हेल्थ जोन के संस्थापक डॉ अनिल गुप्ता जो कि वैदिक विज्ञान में पी एच डी भी है विगत 8 वर्षो से क्वांटम मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे है और सम्पूर्ण स्वास्थ्य के प्रति एक अनूठी पहल करते हुए आधुनिक चिकित्सकिय मशीनों,आयुर्वेद की जीवनशैली,नेचुरोपैथी का उपचार ,हीलिंग थेरेपी एवं राग,रंग और नाद पर आधारित अध्यात्मिक चिकित्सा को समाहित किया है।

विशिष्ठ अतिथि छग योग आयोग के सचिव श्री एम एल पाण्डेय ने कहा की छग योग आयोग को गर्व होता है की हमारे पास डॉ अनिल गुप्ता और डॉ मृत्युंजय राठोर जैसे चिकित्सक हो जो एलोपैथ के विशेषग्य होने के बावजूद देश विदेश में हमारी योग आयुर्वेद और वैदिक जीवनशैली के ज्ञान को वैज्ञानिकता के साथ प्रमाणित करते हुए प्रचार प्रसार कर रहे है।

महावीर नैचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर एस.के श्रीवास्तव ने कहा की डॉ अनिल का कांसेप्ट के साथ पाजीटिव हेल्थ जोन की मशीने हमारी इस विधा को सम्बल प्रदान करेगी हम इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए उत्सुक रहेगे।

संस्था के कोऑर्डिनेटर डॉ. नरेन्द्र पाण्डेय ने बताया की यहाँ उपलब्ध **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

चावलों के निर्यात पर पाबंदी जारी रख सकती है सरकार!

नई दिल्ली। भारत सरकार कम से कम इस साल नवंबर तक गैर-बासमती सफेद चावलों के निर्यात पर पाबंदी जारी रख सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी सूत्रों ने बताया, खरीफ फसलों पर अलनीनो के असर के डर से सरकार ये फैसला ले सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया, इस बात को लेकर पूर्वानुमान किए जा रहे हैं कि खरीफ फसलों पर अल नीनो का असर क्या होगा! सरकार इसे लेकर सचेत है। अगर अल नीनो का असर हो तो सरकार उसके लिए पहले से तैयार है।

सरकार चावलों के निर्यात से पाबंदी हटाने पर तभी विचार करेगी जब खरीफ की बुआई का सीजन खत्म हो जाएगा। इससे सरकार यह अंदाजा लगा पाएगी कि इस साल चावलों की पैदावार कैसी रहेगी। सरकारी अधिकारी ने बताया, मानसून फसल की पैदावार को देखने के बाद ही सरकार पाबंदी हटाने का फैसला करेगी।

क्या है चावल का रेट

7 अगस्त तक रिटेल मार्केट में चावल की कीमत पिछले एक साल में 10.63 फीसदी बढ़ चुकी है जबकि थोक मार्केट में इस दौरान चावल की कीमतों में 11.12 फीसदी का इजाफा हुआ है।

सरकार ने 20 जुलाई को कुछ खास तरह के चावलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। इसके साथ ही सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत कुछ जरूरी कमोडिटी की कीमतों में भी कमी लाएगी। सरकार ने अनाजों का रिजर्व प्राइस भी घटा दिया ताकि बोली में बेहतर रिस्पॉन्स मिल सकें।

अल नीनो का खतरा बरकरार

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जून 2023 के अपने मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट में लिखा है कि अल नीनो की वजह से सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अल नीनो हर 3-6 साल के बीच नजर आता है। इसमें समुद्र के ऊपर जरूरत से ज्यादा गरमी होती है जिसकी वजह से हवाओं का पैटर्न बदल जाता है। इसका असर दुनिया भर के तापमान पर होता है। अमेरिकी सरकार की नेशनल ओसनिक एंड ऑटमॉसफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही यह संकेत दिया था कि इस साल अल नीनो के हालात पैदा हो सकते हैं।

31 जुलाई को भारतीय मौसम विभाग (इम्ड) ने कहा था कि अगस्त में भारत में सामान्य से कम मानसून की बारिश हो सकती है। फिलहाल भूमध्य प्रशांत क्षेत्र में कमजोर अल नीनो की स्थिति बनी हुई है। ताजा मॉडल से संकेत मिल रहा है कि इन कंडीशंस से आगे हालात बिगड़ सकते हैं जो अगले साल तक जारी रहेंगे।

छत्तीसगढ़ में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए व्यापक संभावनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए 'वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना के लिए 'द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' को पांच एकड़ जमीन देने की घोषणा की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना आईसीएआई द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आईसीएआई के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन ''उत्कर्ष'' के दूसरे दिन अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन ''उत्कर्ष'' को सम्बोधित किया

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि किसी भी राज्य और देश की आर्थिक प्रगति में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के आईने की तरह होते हैं, जो उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति को दिखाने का काम करते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मार्गदर्शन देकर अपना योगदान देते हैं। अधिवेशन के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए उसके लिए अच्छा वातावरण तैयार करने की जरूरत होती है। आईसीएआई नवा रायपुर में वर्ल्ड क्लास इंस्टिट्यूट बनाना चाहता है, इसके लिए राज्य सरकार जमीन देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ राज्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ में पिछले पौने पांच वर्षों में कृषि, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में उत्साहजनक वातावरण निर्मित हुआ है। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति से नए-नए उद्योग धंधे प्रारंभ हुए हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य के लोगों के चेहरे की मुस्कान है। लोगों के सपनों को उड़ान देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए नवा रायपुर में 1000 एकड़ में एशिया के सबसे बड़े होल सेल मार्केट की स्थापना की जाएगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रथम एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश तथा गौहाटी हाइकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सूरजमल गर्ग, आईसीएआई के वाइस प्रेसीडेंट श्री रंजीत कुमार अग्रवाल, लल्लूराम न्यूज़ के फाउंडर श्री नमित जैन तथा सेंटर कॉसिल के मेंबर्स विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन किया।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रथम एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सूरजमल गर्ग ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। आज छत्तीसगढ़ देश के किसी भी अच्छे राज्य से स्पर्धा कर सकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज और अच्छे इंस्टिट्यूट्स की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया।

जीएसटीएन ने शुरू की नए प्रबंधित सेवा प्रदाता की तलाश

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने जीएसटी को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए नए सेवा प्रदाता की तलाश शुरू कर दी है। इंफोसिस का प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने का अनुबंध सितंबर 2024 में समाप्त होने वाला है।

परामर्श कंपनी को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और जीएसटीएन की आईटी सेवा का किसी अन्य प्रौद्योगिकी कंपनी में निर्बाध स्थानांतरण सुनिश्चित करना होगा। ऐसी कंपनी जो एक अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले अगले सात वर्षों तक जीएसटी प्रणालियों के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रदान करेगा।

अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी एक जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। इसे लागू करने से पहले सितंबर 2015 में इंफोसिस को जीएसटी नेटवर्क के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण करने का काम सौंपा गया था।

जीएसटीएने एक बयान में कहा, '' जीएसटी प्रणाली के विकास, संवर्द्धन व संचालन के लिए वर्तमान प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) के अनुबंध की अवधि पूरी होने वाली है।

जीएसटीएन एक अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले सात वर्षों के अगले कार्यकाल के दौरान जीएसटी प्रणाली के संचालन के लिए एमएसपी नियुक्त करने के वास्ते बोली लेना चाहता है।'' बोली दाखिल करने की अंतिम तारीख पांच सितंबर है। इंफोसिस को इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए ईमेल भेजा गया, लेकिन खबर लिखने तक उसका कोई जवाब नहीं मिला।

5 नकदी फसलों से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार

नीति आयोग से मांगे सुझाव

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने चाय और तंबाकू जैसी पांच नकदी फसलों से संबंधित विधेयकों के मसौदे पर विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग से सुझाव मांगे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने चाय, कॉफी, मसाले, रबर और तंबाकू की नकदी फसलों से संबंधित विधेयकों के लिए अलग-अलग सुझाव मांगे हैं। इन विधेयकों का मकसद नकदी फसलों से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना और व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।

सलाह लेने के बाद वाणिज्य मंत्रालय इन विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। इनके नाम मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक, रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, चाय (संवर्धन और विकास) विधेयक और तंबाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक हैं।

वाणिज्य विभाग ने 2022 में इन क्षेत्रों के दशकों पुराने कानूनों को निरस्त करने और उनके विकास को बढ़ावा देने और व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा था।

अधिकारी ने कहा, इससे पहले नीति आयोग ने इन पांच विधेयकों पर मंत्रालय के साथ कुछ मुद्दे उठाए थे। अब सभी मुद्दों का समाधान हो गया है।

वाणिज्य मंत्रालय ने चिंताओं को दूर करने के लिए इन मसौदा विधेयकों पर हितधारकों से परामर्श किया था।

कंटेंट क्रिएटर्स को देना होगा टैक्स

एक्स से कमा रहे पैसा तो जीएसटी की आप पर भी नजर

नई दिल्ली। सोशल मीडिया कंपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) से विज्ञापन राजस्व साझाकरण योजना के तहत यूजर्स को मिलने वाली आय को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर देना होगा। विशेषज्ञों ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की किराये से आय, बैंक सावधि जमा पर ब्याज और अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज सहित विभिन्न सेवाओं से कुल आय एक वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो उस पर टैक्स लगेगा।

हाल ही में, एक्स ने अपने प्रीमियम ग्राहकों या सत्यापित संगठनों के लिए विज्ञापन राजस्व साझा करना शुरू किया है। इस राजस्व साझाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अकाउंट में पिछले तीन महीनों में पोस्ट पर 1.5 करोड़ 'इंप्रेशन' और कम से कम 500 'फॉलोअर्स' होने चाहिए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने हाल ही में एक्स से राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने के बारे में ट्वीट किए हैं।

कितनी इनकम पर कितना लगेगा टैक्स?

विशेषज्ञों ने कहा कि 20 लाख रुपये की सीमा की गणना के लिए ऐसी आमदनी को शामिल किया जाएगा जो आमतौर पर जीएसटी से मुक्त हैं। हालांकि, छूट वाली आय पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वर्तमान में, 20 लाख रुपये से अधिक की सेवाओं से राजस्व या आय अर्जित करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं माल और सेवा कर पंजीकरण लेने के लिए पात्र हैं।

मिजोरम, मेघालय, मणिपुर जैसे कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बैंकों से सालाना 20 लाख रुपये की ब्याज आय अर्जित करता है, और जो न तो त्रस्ज्ञ का भुगतान करता है और न ही जीएसटी पंजीकरण कराया है।

उन्होंने आगे कहा कि अब, यदि वह व्यक्ति ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से कोई अतिरिक्त कर योग्य आय, मान लीजिए एक लाख रुपये हासिल करता है, तो उसे जीएसटी पंजीकरण कराना होगा और 20 लाख रुपये से ऊपर की रकम यानी एक लाख रुपये पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि कंटेंट मेकर्स ट्विटर से आय हासिल करता है तो वह जीएसटी के तहत 'सेवाओं का निर्यात' मानी जाएगी, क्योंकि ट्विटर भारत से बाहर है और परिणामस्वरूप, आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर है।

लैपटॉप के बाद कैमरा-प्रिंटर पर सरकार की नजर, इम्पोर्ट पर लग सकता है बैन

नई दिल्ली। पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के बाद सरकार इसी तरह के प्रतिबंध कैमरा, प्रिंटर और हार्ड डिस्क समेत टेलीफोन और टेलीग्राफिक डिवाइस के पार्ट पर भी लगा सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन उत्पादों की हाई लोकल डिमांड और उनके बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट को देखते हुए सरकार घरेलू उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए,हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इन उत्पादों का आयात 10 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा है। इसके अलावा सरकार यूरिया, एंटी-बायोटिक्स, टर्बो-जेट्स, लिथियम आयन एक्युमुलेटर, रिफाइंड कॉपर, मशीन और मैकेनिकल उपकरण, सूरजमुखी के बीज जैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होने वाले उत्पादों का भी मूल्यांकन कर रही है।

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल व्यापारिक आयात 714 अरब डॉलर था, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16.5 प्रतिशत अधिक है। इम्पोर्ट बढ़ने के साथ चालू खाता घाटा बढ़ गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी के 2 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध

इससे पहले सरकार ने पिछले सप्ताह लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात के लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। यह अनिवार्यता 1 नवंबर, 2023 से लागू होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में पीसी, लैपटॉप और टैब्लेट का आयात 5.3 अरब डॉलर का रहा। दूसरी तरफ, वाई-फाई डोंगल, स्मार्ट कार्ड रीडर्स और एंड्राइड टीवी बॉक्स का आयात 2.6 अरब डॉलर का रहा।

सरकार खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर लगाएगी पाबंदी

नई दिल्ली। सरकार इस साल उपभोक्ता वस्तुओं, रबड़, कागज और हल्के इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए 60 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लाएगी। इस पहल का मकसद खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात पर लगाम लगाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर आदेश 'काफी बड़े पैमाने पर' जारी किये जा रहे हैं। अब तक एसी, रेफ्रिजरेटर, पाइप और सुरक्षा वाल्व जैसे 127 से अधिक उत्पादों के लिए 33 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किये गए हैं।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ''फिलहाल, हम भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सहयोग से 60 नये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर काम कर रहे हैं। यह न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये बल्कि गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिये भी महत्वपूर्ण हैं।''

प्रथम पृष्ठ का शेष

भारत पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र, दूसरे देशों को सीखने की जरूरतः डब्ल्यूएचओ

आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, एस्पिरिन और आर्टेमिसिनिन जैसी दवाओं की खोज पारंपरिक चिकित्सा से हुई है।

भारत की तरह एकीकृत चिकित्सा पर करें काम

डॉ. गैब्रेयसस ने कहा कि एकीकृत चिकित्सा को लेकर भारत ने अपने अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर काफी अच्छा मॉडल तैयार किया है, जिसे विकसित और विकासशील देश भी अपना सकते हैं। यह एक ऐसा मॉडल है, जिसके जरिये सदस्य देश अपनी आबादी को एक ही छत के नीचे एलोपैथी और पारंपरिक चिकित्सा दोनों की सुविधा दे सकते हैं।

170 देश पारंपरिक औषधियों का कर रहे इस्तेमाल

डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि आज भी दुनिया के 170 देश पारंपरिक औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका लाभ करीब 80 फीसदी आबादी किसी न किसी रूप में ले रही है। इससे पता चलता है कि ये चिकित्सा पद्धतियां आज के आधुनिक युग में भी कारगर हैं और भारत में इन्हें बहुत अधिक महत्व भी दिया जाता है।

अनुमान है कि सभी देशों में से 88त्र पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं, जैसे हर्बल दवाएं, एक्यूपंक्चर, योग, स्वदेशी उपचार और अन्य। एक सौ सत्तर सदस्य राज्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग की रिपोर्ट करते हैं, और डब्ल्यूएचओ से उनका प्राथमिकता अनुरोध सुरक्षित, लागत प्रभावी और न्यायसंगत उपयोग के लिए नीतियों, मानकों और नियामक ढांचे को सूचित करने के लिए साक्ष्य और डेटा के लिए है।

पारंपरिक चिकित्सा दुनिया भर के समुदायों में सदियों से स्वास्थ्य के लिए एक अभिन्न संसाधन रही है, और पारंपरिक चिकित्सा तक पहुंच में असमानता वाले कुछ लोगों के लिए यह अभी भी मुख्य आधार है। पारंपरिक चिकित्सा की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथा और जैव विविधता विरासत समावेशी, विविध सतत विकास के लिए अमूल्य संसाधन हैं। पारंपरिक चिकित्सा भी बढ़ते खरबों डॉलर के वैश्विक स्वास्थ्य, कल्याण, सौंदर्य और फार्मास्युटिकल उद्योगों का हिस्सा है। 40त्र से अधिक फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन प्राकृतिक उत्पादों और ऐतिहासिक दवाओं पर आधारित हैं, जिनमें एस्पिरिन और आर्टेमिसिनिन शामिल हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा से उत्पन्न हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा के योगदान को अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया है, क्योंकि लाखों मान्यता प्राप्त पारंपरिक चिकित्सा कार्यकर्ता, सुविधाएं, व्यय और उत्पादों का पूरा हिसाब नहीं दिया जाता है। इन ज्ञान आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए WHO की क्षमताओं को बढ़ाना WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (त्रष्टज्ञरू) का मुख्य उद्देश्य होगा।

फ़ायदे

आयुष प्रणालियों को दुनिया भर में स्थापित करना

पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करना।

पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना।

विश्लेषणात्मक कार्य करते हुए डेटा एकत्र करने और प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रासंगिक तकनीकी क्षेत्रों, उपकरणों और पद्धतियों में मानदंड, मानक और दिशानिर्देश विकसित करना। मौजूदा टीएम डेटा बैंकों, आभासी पुस्तकालयों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का एक सहयोगी बनाने वाले डब्ल्यूएचओ टीएम सूचना विज्ञान केंद्र की परिकल्पना करें।

उद्देश्यों की प्रासंगिकता के क्षेत्रों में विशिष्ट क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना और परिसर, आवासीय या वेब-आधारित और डब्ल्यूएचओ अकादमी और अन्य रणनीतिक भागीदारों के साथ साझेदारी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

भारत का निवेश

डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में प्रमुख निवेशक के रूप में, भारत ने केंद्र की स्थापना, बुनियादी ढांचे और संचालन का समर्थन करने के लिए अनुमानित 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें 2024 में एक नए भवन और परिसर के लिए जामनगर, गुजरात, भारत में 35 एकड़ भूमि, एक अंतरिम कार्यालय और 10 साल की प्रतिबद्धता के साथ जीसीटीएम परिचालन लागत के लिए समर्थन शामिल है।

डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एक सुलभ, पर्यावरण-अनुकूल और इंटरैक्टिव सुविधा होगी जो पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति को प्रदर्शित करेगी। जबकि नया केंद्र बनाया जा रहा है, इंस्टीट्यूट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (आईटीआरए) में एक अंतरिम कार्यालय स्थापित किया जाएगा, जो एक डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।

औरा,चक्रों और नाड़ी परीक्षण हुआ आसान

मशीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के और, शरीर के अदृश्य ऊर्जा केन्द्रों,चक्रों,एवं नाड़ी आदि का स्केन करते है। इस परिक्षण से भविष्य में होने वाले बीमारियों की सम्भावन का पूर्व में ही पता चल जाता है। संस्था में उपलब्ध आयुर्वेद विशेषज्ञों,प्राकृतिक चिकित्सकों के मार्गदर्शन पर केरल के टेक्निशयनो द्वारा पंचकर्म की सुविधा भी है। डॉ.अनिल गुप्ता के विशिष्ट पद्धति सायको न्यूरोबिक्स,न्यूरोबिक स्पा एवं न्यूरो लिंगविस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा कई मनोविकारो का निदान किया जाता है एवं सरल और आधुनिक ध्यान की तकनिकी द्वारा मन को संयमित कर मन,मस्तिष्क,शरीर और आत्मा के मध्य संतुलन बनाकर सम्पूर्ण स्वस्थ रहना सिखाया जा रहा है।

अतिथियों ने डिवाइन अर्थ के द्वार मिलेट्स के विभन्न व्यंजनों को आनन्द भी लिया इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर सृजन अग्रवाल ने जानकारी दी वे स्वयं पेट आदि से सम्बन्धित कुछ गम्भीर रोग से ग्रसित थे डाक्टरों ने जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी ,जानकारी जुटाने पर मुझे मिलेट्स की जाकारी प्राप्त हुई और मिलेट्स मैंन खादरवाल्लीजी के मार्गदर्शन पर हम मिलेट्स के उपयोग और जागरूकता पर कार्य करना शुरू कर दिया आज हम अपनी संस्था डिवाइन किचन के माध्यम से सम्पूर्ण वैदिक पद्धति द्वारा लोगो को पवित्र ,स्वादिस्ट एवं स्वस्थ भोजन बनाना सिखा रहे है जिसमे मिट्टी के बर्तन ,गोबर गैस,कच्ची घानी के तेल और कुटे हुए मसाले शामिल है। हमारा उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ स्वाद पहुंचान है इसलिए अब हम डॉ अनिल के positive health zone के साथ मिकर कार्य कर रहे है।

सेंटर में वी एन मिश्रा एवं आर.एन. शर्मा द्वारा कुछ आधुनिक हीलिंग डिवाइसेस का प्रदर्शन कर उसके प्रयोग और लाभ के बारें में जानकारी डी गई। कार्यक्रम की शुरुआत नेत्र परिक्षण से हुई जिसमे श्री गणेश विनायक फाउंडेशन के द्वारा संचालित सर्व सुविधायुक्त मोबाइल वैन में लोगो ने अपना नेत्र परिक्षण कराकर चश्मे का नम्बर प्राप्त किया। फाउंडेशन के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया की यह वैन दुर्ग जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रति दिन भ्रमण क्र लोगो के आँखों का निशुल्क परिक्षण कर रहे है।

अंत में कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु ब्रांच के संचालक विपिन बाफना,ब्रांच इंचार्ज सुभाष मौर,प्राकृतिक चिकित्सक डॉ भूमिका ने साहू ने योग आयोग से आये डॉ भगवंत सिंह,डॉ छाबिराम साहू,डॉ.रविकान्त कुम्भकार,डॉ.ज्योति साहू,प्राची भट्टाचार्य,सहित सभी गणमान्य लोगो का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ.अनिल ने रायपुर positive health zone की प्राकृतिक चिकित्सक डॉ संस्कृति सिंह,जनसम्पर्क अधिकारी डॉ स्मृति सिंह,योग प्रशिक्षक नागेन्द्र साहू,भुनेश्वरी,अंजु-जोमन(केरल के पंचकर्म थेरेपिस्ट),रिंकी,दामनी,गोलू,सत्यभाम,लक्ष्मी सहित कार्यक्रम व्यवस्था समिति के संदीप तिवारी,लिपिका,तेज ,संतोष, कैमरामन (रोहित और पुष्पेन्द्र) एवं नेत्र परिक्षण टीम की सराहना की।

जिंदगियाँ लील रहा है, साइबर अपराध का बढ़ता दायरा

डॉ. शुभ्रा सान्याल
रिटा. प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ क्रिमिनोलाजी एंड फोरेंसिक साइंस, एमएचए दिल्ली

डॉ. शारदा प्रसाद
रिटा. पुलिस महानिदेशक असम मेघालय

डॉ. अभिषेक पल्लव
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम छत्तीसगढ़

सुरेश मेनन
मैनेजिंग पार्टनर लिओनिस कन्सलटेंसी (एलएलपी) साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुंबई

डॉ. अपराजिता भट्ट
असि. प्रोफेसर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली

डॉ. मधुलिका शर्मा
रिटा. डायरेक्टर फोरेंसिक लैब नई दिल्ली

डॉ. अरविन्द चतुर्वेदी
पुलिस अधीक्षक विजीलेंस लखनऊ (उ.प्र.)

राजपाल दाबास
एसीपी दिल्ली

इंटरनैट आजकल हमारी आदत व जरूरत दोनों बन चुका है. औनलाइन शौपिंग, औनलाइन फूड, औनलाइन फ्रैंडशिप, सोशल मीडिया आदि सब बहुत तेजी से आम लोगों की आदतों में शामिल हो चुके हैं. यहां तक कि अब ज्यादातर लोग बैंकिंग भी औनलाइन ही करना पसंद करते हैं. लोगों को अपनी दिनचर्या में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाना इंटरनैट के अधिक इस्तेमाल का एक मूल कारण है.अपनी जीविका कमाने के लिए भागदौड़ करने वाला एक परिवार अपने बच्चों को भी औनलाइन ट्यूशन पर ही जोड़ देता है. ऐसे में जब आप पूरी तरह से इंटरनैट पर निर्भर रहते हैं तो आप बहुत सी ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं जिन से आप का फोन, आप का बैंक अकाउंट, आप का कंप्यूटर, आप का डाटा सुरक्षित नहीं रहता है. आइए समझते है कि किस तरह से कुछ छिपे चेहरे हमारे कंप्यूटर के जरिए हमारी निजी जिंदगी में झांक रहे हैं.

लगातार साइबर क्राइम की शिकायतें पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही हैं. आम तो आम खास लोग भी आज टैक्नोलौजी की दुनिया में खुद की गतिविधियों को हैक होने से नहीं बचा पा रहे हैं.आज साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अपराधी आप के साथ ठगी कर के निकल भी जाता है और आप को उस की भनक भी नहीं लगती. **काव्या फाउण्डेशन और एससीजी न्यूज के सहयोग से लाइफवर्सिटी एक जागरूकता अभियान 'मस्तक पर दस्तक'** की सीरीज लाया है जिसके सभी विडिओ आप https//www.youtube.com/@lifecampus1836 पर देख सकते है

आइए पहले समझते हैं कि किस किस तरह से ये ठग बिना अपना चेहरा दिखाए आम जनता को ठगते हैं.और जानते है सुझाव देश के जाने माने साइबर एक सपर्ट, क्रीमनल सायकोलाजिस्ट,मनोवैज्ञानिक,लॉ प्रोफेशनल,सायबर सेल के पुलिस अधिकारी आईटी के जानकारों से –

हैकिंग– 'हैलो मैम, आप हमारी

10 लकी कस्टमर में से हैं. हमारी कंपनी की तरफ से आप को एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा. आप को बस, हमारे द्वारा भेजे हुए लिंक पर क्लिक कर के एक फौर्म फिल करना है और उस के बाद आप के फोन पर एक ओटीपी आएगा. वह हम से शेयर करना है. आप का सरप्राइस गिफ्ट आप के घर पर डिलीवर हो जाएगा'.

इस तरह के फोन कर के आप को लिंक मेल कर के आप के कंप्यूटर पर आए मेल और आप के फोन पर आए ओटीपी के माध्यम से हैकर्स आप के फोन को हैक कर देते हैं. हैकिंग ऐसी प्रक्रिया है जिस में कोई व्यक्ति गैरकानूनी रूप से किसी व्यक्ति की निजी जानकारियों में बिना अनुमति के घुस जाता है. उन के जरिए वे उन की वैबसाइट की सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और पूरी तरह से हैक कर सकते हैं. इस के अलावा, वे उन के सोशल मीडिया एक्सेस को भी हैक कर के उन की पहचान को इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस क्राइम की सब से बड़ी बात तो यह है कि उस कंप्यूटर या फोन औनर को भी इस बात का पता नहीं चलता है कि कोई हैकर उस के कंप्यूटर या फोन में मौजूद सभी प्रकार की जानकारी इस्तेमाल कर रहा है और उस के ही नाम से चला रहा है. यहां तक कि औनलाइन बैंकिंग की भी सारी जानकारी हैकर्स के पास है और वह जब चाहे आप के बैंक को खाली कर सकता है.

यह एक साधारण सा दिखने वाला साइबर अपराध है पर इस का अंजाम बुरा हो सकता था. इंटरनैट, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को धमकाना, किसी व्यक्ति को गैरकानूनी कार्य करने के लिए कहना, किसी व्यक्ति का मजाक बनाना जिस से उस की भावनाओं पर ठेस पहुंचे आदि सब को साइबर बुलिंग कहते हैं.

फिशिंग–फिशिंग के जाल में फंसने वाले राहुल, जो कि दिल्ली से हैं, कहते हैं, "मुझे एक बड़ी कंपनी से जौब का औफर आया था. उस के साथ एक एप्लीकेशन फौर्म था जिस को पूरा भर कर अपने महत्त्वपूर्ण कागज लगा कर मैं ने उसी ईमेल पर मेल किए थे पर कुछ दिनों बाद ही मुझे समझ आ गया कि जरूर कुछ दिक्कत है. मुझे मेरे फोन नंबर पर ओटीपी आने लगे. मुझे समझ नहीं आ रहा था.

"मेरा फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक था. मैं ने एक जानकार से पूछा इन ओटीपी के बारे में तो सम?ा आया मेरा आधार कार्ड सामान एक्सपोर्ट होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मेरा फोन हैक है तो ओटीपी भी आसानी से हैकर को मिल रहे हैं. मैं ने तुरंत 1930 (नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हैल्पलाइन नंबर) पर शिकायत की."

अगर आप भी अपने ईमेल बौक्स को चैक करते हैं तो आप भी अकसर वहां स्पैम ईमेल देखते होंगे. दरअसल फिशिंग का प्रमुख कारण स्पैम ईमेल का उपयोग है. फिशिंग के तहत साइबर क्रिमिनल द्वारा यूजर को स्पैम ईमेल भेजी जाती है जहां लिंक पर या अटैचमैंट पर क्लिक कर के आप के सिस्टम को हैक किया जा सकता है. साथ ही, यहां आप को स्पैम वैबसाइट का लिंक भी दिया जा सकता है जिस पर आप को अपनी जानकारियां भरने को कहा जाता है. अपनी निजी एवं बैंकिंग संबंधित जानकारियां भरने पर आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं.

साइबर बुलिंग–10वीं क्लास के एक स्टूडैंट ने अपने साथ पढ़ने वाली एक छात्रा को कार्ड गिफ्ट किया. उस छात्रा ने उस कार्ड को ठुकरा दिया. यह बात उस स्टूडैंट ने अपने कैमरे में रिकौर्ड कर पूरे स्कूल में फैला दी. इस से वह छात्रा आहत हुई और उस ने अपने घर पर फिनायल पी कर जान देने की कोशिश की. अब इस में गलती किस की है?

यह एक साधारण सा दिखने वाला साइबर अपराध है पर इस का अंजाम बुरा हो सकता था. इंटरनैट, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को धमकाना, किसी व्यक्ति को गैरकानूनी कार्य करने के लिए कहना, किसी व्यक्ति का मजाक बनाना जिस से उस की भावनाओं पर ठेस पहुंचे आदि सब को साइबर बुलिंग कहते हैं.

इस के लिए सब से ज्यादा जरूरी है अपने निजी पलों को निजी रखें. बहुत सारे ऐसे लोग, जिन्हें साइबर क्राइम के बारे में पता नहीं होता है, साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं.

सोशल मीडिया से फोटो चुराना– पार्टिसईपेन्ट बताती हैं, "रात 10 बजे मुझे अचानक मेरे एक जानकार का फोन आया कि मैं ने उस से 10,000 रुपए पेटीएम करने को कहा है. मैं थोड़ा हैरान हो गई और मैं ने उस से पूछा कि किस नंबर से मैसेज आ रहा है. उस ने बताया कि नंबर तो जानापहचाना नहीं है पर डीपी में फोटो आप की लगी है और ट्रूकौलर पर नाम भी आप का आ रहा है.

मुझे समझाते देर नहीं लगी कि यह किसी तरह का साइबर अपराध है. मैं ने तुरंत साइबर क्राइम पर फोन किया और शिकायत दर्ज करवाई."

यह तो हुई फोटो लगा कर पैसे मांगने की बात पर साइबर क्राइम के अंतर्गत कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से उस की पिक्चर्स चुरा लेते हैं और उन्हीं पिक्चर्स को ले कर वे उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं. इस के शिकार कई औरतें, लड़कियां और बच्चे होते हैं.

अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो यह अपराध बहुत बड़ा रूप ले चुका है. बड़ेबड़े सरकारी विभागों के कंप्यूटर में वायरस डाल कर सरकारी डाटा चोरी करने का प्रयास भी कई बार सामने आ चुका है. 30 नवंबर, 2022 को इंडियन काउंसिल औफ मैडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की वैबसाइट को 6,000 बार हैक करने की कोशिश की गई.

इस से बचने के लिए क्याक्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, वह जानना बहुत जरूरी है. आजकल हैकर्स जितने चलाक और टैक्निकली मजबूत हो चुके हैं, हमें भी अपने फोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया को सिक्योर करना बहुत जरूरी है. कुछ सावधानियां बरत के हम इस तरह की हैकिंग से बच सकते हैं.

अनजान लिंक पर क्लिक न करें, चाहे वह कितना भी लुभावना नजर आ रहा हो.

अनजान वैबसाइट पर ध्यान न दें.

कोई भी सौफ्टवेयर या ऐप्स को फ्री में इस्तेमाल करने के चक्कर में ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल न करें जो आगे जा कर नुकसान कर सकती है. थर्ड पार्टी ऐप्स वे ऐप्स होती हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं होतीं क्योंकि ये एप्लीकेशन नियमों का उल्लंघन कर रही होती हैं.

निजी जानकारी को पर्सनल ही रखें. आधार कार्ड अपडेट, वोटर कार्ड अपडेट या लिंक या केवाईसी करवाने के नाम से आप से कोई औनलाइन फौर्म भरने को बोले तो पहले अच्छे से जांच लें कि कहीं आप की निजी जानकारी गलत हाथों में तो नहीं जा रही.

औनलाइन स्कीम्स जैसे– आप 10 लक्की कस्टमर में हैं, आप का नंबर कंपनी ने चुना है, फलाने मंदिर में यूपीआई से सीधे औनलाइन पैसा चढ़ाएं जैसी फोन कौल पर भरोसा न करें. आप को लक्की कस्टमर बता कर आप के बैंक अकाउंट खाली कर जाएंगे.

पब्लिक वाईफाई का उपयोग करने से बचें पर फिर भी इस्तेमाल करना पड़े तो वाईफाई इस्तेमाल कर के फोन से उस का आईडी पासवर्ड तुरंत हटा दें और फोन को बंद कर के फिर से चालू करें.

कई लोग अपने औनलाइन डिजिटल वौलेट या सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड बहुत ही आसान रखते हैं, जैसे उन का नाम, फोन नंबर, बच्चों का नाम. इस में हैकर्स बहुत आसानी से उन के अकाउंट को हैक कर लेते हैं. इसलिए, जरूरी है कि आप अपने सारे पासवर्ड थोड़े से मुश्किल रखें.

फिर भी आप अगर किसी तरह के साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं तो साइबर क्राइम की हैल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज जरूर करवाएं.

आध्यात्मिक ही नहीं रक्षाबंधन के हैं चिकित्सकीय फायदे भी

रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करती हैं, लेकिन राखी, कलावा या रक्षा सूत्र बांधने के अध्यात्मिक, वैज्ञानिक और चिकित्सीय फायदे भी बहुत हैं.

रक्षासूत्र में रेशम प्रमुख अवयव माना जाता है। इसे एंटीबायोटिक भी माना जाता है और केशर को ओज़करक, उष्णवीर्य, उत्तेजक, पाचक, पित्त-कफ नाशक और दर्द निवारक गुणों से युक्त माना गया है। सरसों भी अत्यधिक रोगों से बचाव के साथ-साथ यह खुजली और पेट के कीड़ों को नष्ट करने में मददगार साबित होता है। दूर्वा, जिसे डूब भी कहा जाता है, रक्तदोष को कम करने, मूर्छा को दूर करने, अतिसार को नियंत्रित करने, अर्श को बढ़ावा देने, यौन रोगों का उपचार करने, पीलिया से रक्षा करने, उदार रोगों को दूर करने, वमन में मदद करने, मूत्र विकारों को दूर करने आदि में विशेष लाभकारी होता है। चंदन शीतल गुणों से युक्त होता है, जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एन्डोर्फिन को संतुलित करता है। इसलिए रक्षाबंधन की राखी में केसर भाई की ऊर्जा और तेजी को बढ़ावा देता है, अक्षत भाई की सेहत को बेहतर बनाता है, सरसों के दाने भाई की शक्ति को वृद्धि देते हैं, दूर्वा भाई के गुणों में और चंदन भाई के जीवन में आनंद, सुगंध, और शीतलता को बढ़ावा देते हैं। वैदिक मान्यतानुसार हाथ के मूल में तीन रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं. भाग्य व जीवनरेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध है. इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा हैं. इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी साक्षात वास रहता है. जब कलावा कलाई में बांधते हैं तो यह तीन धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है. शरीर विज्ञान अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन रहता है. इससे मन शांत और पवित्रता बनी रहती है. व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते. वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है.

डॉ संस्कृति सिंह (BNYS)

प्राकृतिक चिकित्सक,आहार एवं सौन्दर्य विशेषज्ञ पाज़िटिव हेल्थ ज़ोन,रायपुर (छग),883920609

दिल मिल रहें है मगर डिजिटली चुपके चुपके

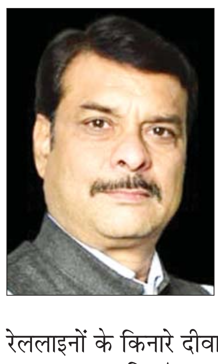

नरेन्द्र पाण्डेय

स्मार्टफोन के दौर में महानगरों से आगे छोटे शहरों और कस्बों तथा दूर-दराज के इलाकों में बाजार तलाश रहे हैं। कुछेक दावों को मानें तो दूसरे-तीसरे दर्जे के शहरों में विवाहेतर सेक्स इच्छाओं की पूर्ति का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है।

कुछ वर्ष पहले तक रिश्तों की तलाश के व्यावसायीकरण की थोड़ी-बहुत या छोटे-मोटे धंधे का एक नजारा रेललाइनों के किनारे दीवार पर लिखा देखा जा सकता था कि, 'एक बार मिल तो लें।' लेकिन अब कई डेटिंग ऐप ने इसे बाकायदा संगठित कारोबार और बाजार की शक्ल दे दी है। ये ऐप बाजार बनाने की तमाम मार्केटिंग रणनीतियां अपनाकर दबी-छुपी लालसाओं, वासनाओं के लिए मौका मुहैया करा रहे हैं। विवाहितों के लिए बने डेटिंग ऐप्स उन लोगों के लिए भी नए दरवाजे खोल रहे हैं, जिन्हें अब तक शादी 'निभाने' की बात लगा करती थी। यह पेशकश भी है कि बिना मिले सिर्फ बात या चैट करके (सेक्सटिंग) भी संतुष्टि पा सकते हैं। ये ऐप इंटरनेट और स्मार्टफोन के दौर में महानगरों से आगे छोटे शहरों और कस्बों तथा दूर-दराज के इलाकों में बाजार तलाश रहे हैं। कुछेक दावों को मानें तो दूसरे-तीसरे दर्जे के शहरों में विवाहेतर सेक्स इच्छाओं की पूर्ति का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। विवाह, विवाहेतर रिश्ते, सुख की विविध आकांक्षाएं, वफा-बेवफाई तो शायद अनादिकाल से हैं। दुनिया भर के साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, महाकाव्य, पौराणिक कथाओं में अनेक तरह के किस्से हमारी याददाश्त का हिस्सा हैं। शायद किसी भी दौर और किसी भी समाज में तमाम तरह की मानव-प्रवृत्तियां सक्रिय रहती हैं, लेकिन ये सब व्यक्तिगत मामले रहते आए हैं। नया कुछ है तो बस आधुनिक बाजार की पैठ। खास बात यह है कि मझोले और छोटे शहरों में इसका आकर्षण बढ़ रहा है। दूसरा चौंकाने वाला संकेत यह है कि विवाहेतर या एकाधिक संबंधों के आकर्षण के मामले में महिलाएं लगभग पुरुषों के बराबर हैं। संभव है, यह मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा हो या फिर रिश्तों की चाहत के मामले में तेजी से टूट रही वर्जनाएं ।

विवाह को पवित्र बंधन मानने वाले भारतीय समाज में इस बंधन के बाहर का कोई भी रिश्ता अस्वीकार्य है। आंकड़े बताते हैं कि कोविड महामारी के बाद आश्चर्यजनक रूप से मझोले और छोटे शहरों में रिश्ते में रहते हुए रिश्ते खोजने वालों की बाढ़ सी आ गई है। महामारी में जब आवागमन के साधन बंद थे, दफ्तरों की जगह घर से काम हो रहा था, मिलने-जुलने पर पाबंदी थी, तब वर्चुअल डेटिंग ने अपने पैर पसार लिए 7 कुछ लोग लॉकडाउन के चलते, तो कुछ नौकरी छूट जाने की वजह से बड़े शहर छोड़ छोटे शहर या कस्बों में अपने घरों को लौट आए और उन लोगों के साथ आई ऐप की रंगीन दुनिया।

भारत में शादीशुदा लोगों के लिए बने इन डेटिंग ऐप ने जिस तरह यहां के लोगों के मोबाइल में जगह बनाई, उसे भले कुछ लोग हजम न कर पाएं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि शादी से उपजी ऊब इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। अब दिल में उसी के लिए जगह है जिसके लिए मोबाइल में जगह है। अब व्यक्ति दिल से बाद में उतरता है, मोबाइल पर पहले ब्लॉक हो जाता है। विवाहेतर संबंधों के बढ़ने की वजह यह हो सकती है कि घर में, सफर में, दफ्तर में, जहां चाहे वहां बैठ कर किसी से भी संपर्क साधा जा सकता है। इंटरनेट ने यह आजादी तो दी ही है कि जो मन करे वह देखो, सुनो। जो लोग लिख-पढ़ नहीं पाते, वे वॉइस सर्च से जो चाहे खोज सकते हैं। ऐसे में कोई ऐप का विज्ञापन सामने आ जाए, तो उत्सुकता में उस पर क्लिक होगा ही। एक बार आप उस पर गए तो यूजर की संख्या में तुरंत इजाफा हो जाएगा। शायद बेवफाई अलग रोमांच और दिलचस्पी जगाती है। बॉलीवुड का भी यह पसंदीदा विषय रहा है लेकिन ये ऐप अब चिट्ठियां लिख कर, आंखों के इशारों से बतियाने या चोरी-छुपे मिलने की झंझट को हाइटेक बना रहे हैं। विश्वासघात से टूटा आदमी अब तुरंत कहीं 'जुड़' (कनेक्ट) जाता है। टूटे हुए बहुत से लोग ऐप्स पर जुड़ने की प्रतीक्षा सूची में रहते हैं। एक साथी के छूट जाने के बाद नए साथी की तलाश नई उम्मीद की तरह हो सकती है, शायद इसी वजह से आजकल अपने प्रोफाइल को बढ़ा-चढ़ा कर बनाना, शानदार तस्वीर खिंचवा कर पोस्ट करना और खुद को इतना प्रेम करने वाला, देखभाल करने वाला बताना आम होता जा रहा है। दरअसल 'मूव ऑन' पीढ़ी ने रिश्ते टूटने या जुड़ने के तनाव को एक झटके में दूर फेंक दिया है। शरीर के साथ प्रेम हो यह जरूरी नहीं मगर प्रेम के साथ शरीर का होना जरूरी है .

शरीर के साथ आपसी आकर्षण का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आकर्षण के साथ शरीरिक संबंध बनाना महत्वपूर्ण होता है। प्यार के बिना भी शारीरिक संबंध आसानी से बनाए जा सकते हैं, और आजकल बाजार में इसके अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। हालांकि, प्यार शरीर के बिना भी संभव है, लेकिन उसका सम्पूर्ण रूप शरीर के साथ ही प्राप्त होता है।

संपादकीय

चावल पर प्रतिबंध का प्रभाव

सरकार ने बासमती तथा उसना चावल को छोड़कर हर प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का यह निर्णय राजनीतिक बाध्यताओं से प्रेरित है। ऐसा शायद इसलिए किया गया है ताकि कुछ अहम राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले घरेलू आपूर्ति और कीमतों का बचाव किया जा सके। परंतु इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें 11 वर्ष के उच्चतम स्तर पर हैं तथा उनमें और इजाफा होने लगा है। कुछ मामलों में तो जो माल रास्ते में है उसकी कीमत भी 50 से 100 डॉलर प्रति टन तक बढ़ गई है। भारत पिछले कुछ समय में दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक रहा है और उसने वैश्विक व्यापार का करीब 40 फीसदी अनाज निर्यात किया। वर्ष 2022-23 में उसने 2.23 करोड़ टन चावल निर्यात किया। उसके अचानक इस बाजार से बाहर हो जाने से वैश्विक आपूर्ति में करीब एक करोड़ टन की कमी आएगी।

गैर खुशबूदार चावल के अन्य निर्यातकों में थाईलैंड और वियतनाम के पास इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त चावल का भंडार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जो पहले ही मौसम के कारण उपज से जुड़ी अनिश्चितताओं, रूस द्वारा यूक्रेन को काला सागर बंदरगाहों के जरिये अनाज निर्यात की इजाजत वापस लेने के कारण बढ़ी हुई थीं उनमें और तेजी आई है। इससे खाद्यान्न संकट से जूझ रहे देशों की चिंताएं बढ़ेंगी। खासतौर पर छोटे अफ्रीकी देशों की जो भारत से आने वाले अनाज पर निर्भर करते हैं।

आश्चर्य नहीं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत द्वारा निर्यात प्रतिबंध को लेकर आक्रामक रुख दिखाया और कहा कि इससे वैश्विक खाद्य कीमतों की अस्थिरता की स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने भारत से कहा है कि उसे यह प्रतिबंध हटा लेना चाहिए। देश में भी सरकार के कदम को समझदारी भरा नहीं माना जा रहा है।

इसकी कई वजह हैं। एक बात तो यह कही जा रही है कि ऐसा करके भारत आकर्षक वैश्विक कीमतों से फायदा उठाने से चूक रहा है। इसके अलावा यह इस लिहाज से भी नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि किसान धान की खेती का रकबा बढ़ाने को लेकर हतोत्साहित होंगे और वे उपज बढ़ाने वाले साधनों का प्रयोग भी नहीं करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे खाद्यान्न के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता और विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार की भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा।

इसमें दो राय नहीं है कि चावल की घरेलू कीमतों में साल भर में करीब 11.5 फीसदी का इजाफा हुआ है लेकिन इस इजाफे की एक वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा भी है। निश्चित रूप से स्थानीय बाजारों में चावल की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम के कुल अनाज भंडार में कमी आई है लेकिन चावल का भंडार अभी भी 4.1 करोड़ टन से अधिक है यानी 1.35 करोड़ टन की बफर स्टॉक सीमा से काफी अधिक। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकार की 3.6 से 3.8 करोड़ टन की आवश्यकता से काफी अधिक है।

यह आशंका भी कमजोर हुई है कि उभरते अल नीनो प्रभाव के कारण मॉनसून तथा धान की खेती प्रभावित होगी। अब तक तो मॉनसून देश भर में सामान्य से बेहतर रहा है और धान की बोआई उन इलाकों में भी काफी अच्छी है जहां पिछले साल यह इस समय कमजोर रही थी। ऐसे में सरकार को यही सलाह होगी कि वह बाजार को ऐसे झटके देने वाले निर्णय न ले और यह सुनिश्चित करे कि घरेलू और बाहरी खाद्यान्न व्यापार नीतियों में स्थिरता बरकरार रहे।

अर्थव्यवस्था के सामने बेरोजगारी की चुनौती ?

सरोज कुमार

कृषि अर्थव्यवस्था का इकलौता क्षेत्र है, जो घाटे के बावजूद बंद नहीं होता। यहां श्रमशक्ति का लगभग 45-50 फीसद हिस्सा रोजगार पाता है। कृषि क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार मौसमी होते हैं। फिर भी इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए तो भारत की बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है।

कोई अवस्था लंबी अवधि तक बनी रहे तो उसके प्रति सहज भावना पैदा होने लगती है। यह सहजता धीरे-धीरे स्थायी हो जाती है। एक सीमा के बाद दर्द का अहसास न होना इसी प्रक्रिया का परिणाम है। बेरोजगारी के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्थायी भाव अच्छा संकेत नहीं है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक औसत बेरोजगारी दर 7.6 फीसद के उच्चस्तर पर बनी रही। लेकिन कहीं से कोई खास विमर्श का स्वर सुनाई नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि शायद बेरोजगारी का अहसास जाता रहा! यह मानव मन में बेरोजगारी के सहज हो जाने का संकेत है। बेरोजगारी का स्थायी भाव अस्थिरता है। यानी बेरोजगारी जितनी स्थायी होगी, अस्थिरता उतनी ही बढ़ती जाएगी।

अस्थिरता का कुछ करती है, बताने की जरूरत नहीं। मनोभावों के बदलने से आंकड़े नहीं बदलते। अलबत्ता आंकड़े मनोभावों को बदल देते हैं। बेरोजगारी का सवाल आंकड़ों से आगे का है और मानव मन आज इसी सवाल में उलझ कर रह गया है। बेरोजगारी के आंकड़े इतने भारी हो गए हैं कि अब इन्हें न तो मानव मन ढो पाने की स्थिति में है, और न अर्थव्यवस्था ही। 'सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी' (सीएमआइई) के अनुसार, बीते वित्त वर्ष में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक की औसत मासिक वृद्धि दर 2.68 फीसद रही।

इस धीमी वृद्धि दर का परिणाम है कि उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक महामारी से पूर्व के स्तर पर आज तक नहीं पहुंच पाया। मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक भी उस स्तर पर पहुंचने की संभावना कम है। महामारी से ठीक पहले फरवरी 2020 में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक 105.3 पर था, जो मार्च 2023 में 89.18 पर दर्ज किया गया। मानसून पर संभावित अल नीनो प्रभाव और निजी निवेश में अनवरत सुस्ती के मद्देनजर मौजूदा वित्त वर्ष में भी उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक का संभवतः यही हाल रहने वाला है।

उपभोक्ता मनोभाव का ऊपर उठना आमदनी पर निर्भर करता है और ऊंची बेरोजगारी दर इसकी संभावना को धूमिल कर देती है। जाहिर है, इसका असर अर्थव्यवस्था पर होगा और अर्थव्यवस्था का असर मानव जीवन पर, सामाजिक ताने-बाने पर। बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 4.4 फीसद रह गई और चौथी तिमाही में इसके और नीचे जाने की आशंका है।

वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच मौजूदा वित्त वर्ष का परिदृश्य भी सुखद नहीं है। वैश्विक वित्तीय एजंसियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान घटा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने 6.1 फीसद के अपने अनुमान को घटाकर 5.90 फीसद कर दिया। विश्व बैंक ने 6.6 फीसद के अनुमान को घटाकर 6.3 फीसद और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने अपने अनुमान को 7.2 फीसद से घटाकर 6.4 फीसद कर दिया है।

नोमुरा के अनुसार, भारत की वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष में 5.3 फीसद रहनी है। बेशक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने मौजूदा वित्त वर्ष की अपनी पहली नीतिगत समीक्षा में विकास दर अनुमान को 6.4 फीसद से बढ़ाकर 6.5 फीसद किया, लेकिन विशेषज्ञों की नजर में यह अति आशावादी आंकड़ा है।

बेरोजगारी दर के आंकड़े दो प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं- श्रमिक भागीदारी दर और रोजगार सृजन। श्रम बाजार में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ गई और उसके अनुसार रोजगार सृजन नहीं हुआ तो बेरोजगारी दर ऊंची दिखेगी। रोजगार सृजन नहीं भी हुआ, मगर श्रमिक भागीदारी घट गई तो बेरोजगारी दर नीचे दिखेगी। लेकिन यहां तो श्रमिक भागीदारी घटने के बाद भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है।

सीएमआइई के अनुसार, मार्च 2023 में श्रमिक भागीदारी दर घटकर 39.8 फीसद रह गई, जो फरवरी 2023 में 39.9 फीसद थी। लेकिन बेरोजगारी दर फरवरी के 7.5 फीसद से बढ़कर मार्च में 7.8 फीसद हो गई। अप्रैल 2023 में श्रमिक भागीदारी दर और बेरोजगारी दर दोनों में वृद्धि हुई। श्रमिक भागीदारी दर मार्च 2023 के 39.8 फीसद से बढ़कर अप्रैल 2023 में 41.98 फीसद दर्ज की गई और बेरोजगारी दर फरवरी 2023 के 7.8 फीसद से बढ़कर मार्च 2023 में 8.11 फीसद हो गई।

अप्रैल 2023 की श्रमिक भागीदारी दर पिछले तीन सालों में सर्वाधिक है। महामारी की शुरुआत, यानी मार्च 2020 में श्रमिक भागीदारी दर 41.9 फीसद थी और तब बेरोजगारी दर 8.74 फीसद थी। उसके बाद से श्रमिक भागीदारी दर लगातार 41 फीसद से नीचे रही है। अप्रैल 2023 का यह रुझान आगे टिका रहेगा, संभावना कम है।

सवाल उठता है आखिर बेरोजगारी की समस्या स्थायी क्यों होती जा रही है और इसका समाधान क्या है? आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद से भारत का सार्वजनिक क्षेत्र लगातार सिमट रहा है। ऐसे में रोजगार पैदा करने का दारोमदार निजी क्षेत्र पर है। निजी क्षेत्र मुनाफे के लिए काम करता है। निवेश तभी करता है, जब मुनाफे के साथ लागत की वापसी का भरोसा हो।

मुनाफा तभी होगा, जब बाजार में मांग हो। मांग तब होगी, जब लोगों की जेब में पैसे हों। बाजार में आज मांग की स्थिति मंद हो चली है। मांग पर पहली बड़ी मार नोटबंदी और जीएसटी के कारण पड़ी। रही-सही कसर महामारी ने पूरी की। अर्थव्यवस्था में 30 फीसद की और रोजगार में 40 फीसद की हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों पर ताले लगने लगे।

सरकार की तरफ से फरवरी 2023 में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए आंकड़े के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक 17,452 से अधिक एमएसएमई इकाइयां बंद हो गईं। सर्वाधिक 10,655 इकाइयां अकेले 2022-23 में बंद हुईं। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 22,140 करोड़ रुपए का आबंटन किया है, जिसका परिणाम आना अभी बाकी है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति शृंखला बाधित हुई तो महंगाई चरम पर पहुंच गई। मांग को नीचे लाने में इसका भी बड़ा योगदान है। मांग न होने से विनिर्माण क्षेत्र अपनी मौजूदा स्थापित क्षमता का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, नई क्षमता जोड़ना तो दूर की बात। ऐसे में नौकरियों की सृजन प्रक्रिया पर विराम-सा लग गया है।

भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का यह इकलौता क्षेत्र है, जो घाटे के बावजूद बंद नहीं होता। यहां श्रमशक्ति का लगभग 45-50 फीसद हिस्सा रोजगार पाता है। कृषि क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार मौसमी होते हैं। फिर भी इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए तो भारत की बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। सरकार के लिए यह प्राथमिकता का क्षेत्र होना चाहिए।

लेकिन स्थिति इसके उलट है। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र का आबंटन घटा कर कुल बजट का 2.7 फीसद कर दिया गया, जबकि 2022-23 में यह आबंटन कुल बजट का 3.36 फीसद था। धनराशि के मामले में हालांकि आबंटन पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले 4.7 फीसद अधिक है। लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजटीय प्रस्ताव से सात फीसद कम।

दूसरी तरफ कुल श्रमशक्ति के लगभग 12 फीसद हिस्से को रोजगार देने वाले विनिर्माण क्षेत्र के लिए सभी सुविधाएं सुलभ हैं। वर्ष 2016 में आइबीसी कानून लाया गया, सितंबर 2019 में कारपोरेट कर 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद कर दिया गया और महामारी के बीच उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना लाई गई।

मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में पूंजीगत निवेश का आबंटन बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया तो उसका एक बड़ा हिस्सा परोक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को मदद पहुंचाने के लिए है। निजी क्षेत्र फिर भी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा। नीति-नियंताओं को इस नीतिगत विफलता पर नए सिरे से मंथन करना चाहिए और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को समर्थन देकर बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान खोजना चाहिए।

उठो युवा मन जागो

उठो युवा मन जागो अब तो,हर एक दिन जगाओ तुम।
आज ससय के साथ खड़े हो, आगे बढ़ते जाओ तुम।

तेरे साहस के आगे तो , पर्वत बड़ा नहीं होता ।
तेरे साहस के आगे तो, दुश्मन खड़ा नहीं होता ।
तेरे साहस के आगे ही, हर बादल झुक जाता है ।
तूफानों का प्रबल वेग भी , हार मान रुक जाता है ।

अपने वतन की रक्षा में सीना तान अड़ जाओ तुम ।। 1 ।।
आज समय के साथ खड़े हो, आगे बढ़ते जाओ तुम।
उठो युवा मन जागो अब तो,हर एक दिन जगाओ तुम।

तेरे ही सीने में नित नित, शोला एक दहकता है।
तेरे ही सीने में नित नित, पंछी चाह चहकता है।
तेरे भी सीने में नित नित, स्वदेश प्रेम पनपता है।
और स्नेहिल मन की भूमि पर, दैविक सुमन महकता है।

दिलों में तिरंगा फहरा कर , नव इतिहास रचाओ तुम।। 2 ।।
आज समय के साथ खड़े हो, आगे
बढ़ते जाओ तुम।
उठो युवा मन जागो अब तो,हर एक
दिल जगाओ तुम।

श्रवण चोरनेले 'श्रवण'
रायपुर (छत्तीसगढ़)

कुर्बानियों से मिली है आजादी

हमारे देश की आजादी ने 76 लंबे साल पूरे किए हैं। यह कालखंड एक विशाल, विराट इतिहास सरीखा है। गुलामी की बेड़ियां और उनकी पीड़ा बहुत पीछे छूट चुका है। आज हमारा लोकतंत्र आजाद है। संविधान स्वतंत्र और भविष्यद्रष्टा है। हमारे अपने मौलिक अधिकार और मूल्य हैं। आज हम मानसिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर संप्रभु राष्ट्र हैं। संस्कृति और सभ्यता के साथ-साथ एक समृद्ध विरासत, धरोहर भारत ने ही विश्व को दी है, लिहाजा सांस्कृतिक उत्थान में हमारा कोई सानी नहीं है। आज हमारा आसमान और विभिन्न आयाम अनंत और अशेष हैं। हमारी फिजाएं और हवाएं भी अबाध हैं। 15 अगस्त, 1947 को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दौर में हम सुई तक बनाने में अक्षम थे। गांव तक बैलगाड़ी या फिर मीलों पैदल चल कर जाना पड़ता था। सड़कें और राजमार्ग स्वप्निल थे। रेलगाड़ी और यातायात के साधन बेहद सीमित थे और पंगु भी साबित होते रहते थे। भारत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत वाला राष्ट्र था, फिर भी उसे गांव, गरीब, गोबर और सांपों वाला देश माना जाता था। हमने परवाह नहीं की। भारत एक भूखंड ही था, जहां निर्जन, बंजर, पठार, जंगल, मरुस्थल असंख्य थे। हमने उन्हें संसाधनों में तबदील किया। आत्म-संतोष यह था कि अब हम स्वतंत्र, संप्रभु और गणतांत्रिक देश होंगे।

उस और आज के कालखंड की तुलना करें, तो खुद से सवाल करना पड़ता है कि अंतरिक्ष, आसमान, समंदर से लेकर जमीन तक कहां नहीं है हिन्दुस्तान? यह बात पुरानी और सियासी-सी लगती है, लेकिन हकीकत है कि आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तीसरे स्थान तक का सफर बड़ी तेजी से कम हो रहा है। यह हम आजाद भारतीयों के पुरुषार्थ और मेहनत का ही नतीजा है। आज हम दूध और चीनी के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देश हैं। गेहूं, चावल, फल, सब्जियों आदि के संदर्भ में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक और आपूर्तिकर्ता देश हैं। कभी भारत अकाल और खाद्य-संकट वाला देश था। विदेश से 'लाल गेहूं' का जहाज आता था, तो हमें आटा नसीब होता था। हमारी 'हरित क्रांति' ने भारतीय कृषि की दशा और दिशा ही बदल दी। आज चंद्रमा की ओर हमारा 'चंद्रयान-3 मिशन' बढ़ रहा है, तो रूस का भी मिशन वहां पहुंचने वाला है, जबकि रूस हमसे बहुत आगे है। हमने कई देशों के उपग्रह भी अपने अंतरिक्ष अभियान के साथ भेजे हैं। आज अमरीका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की विख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारी स्वदेशी कंपनियों के समन्वय और सहयोग से, भारत में ही, उत्पादन कर रही हैं। भारत इन देशों का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार भी है। लड़ाकू विमान के सबसे ताकतवर इंजन, सेमीकंडक्टर चिप्स आदि का निर्माण भी अब भारत में ही होगा। कभी हम अमरीका, चीन, सिंगापुर आदि देशों पर आश्रित होते थे। आज भारत आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज हम विमान, मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कई अन्य हथियारों का उत्पादन देश में ही कर रहे हैं और 50 से अधिक देशों को हथियारों का निर्यात भी कर रहे हैं। यह भी आश्चर्य ही है कि करीब 140 करोड़ की आबादी वाले विशाल और विविध देश में अकाल, भुखमरी के कोई आसार तक नहीं हैं। हम सभी ने मिल कर कोरोना वैश्विक महामारी को भी मात दी है। हमारे देशवासियो! यह आजादी बेमिसाल है, अद्भुत और दुर्लभ भी है, लिहाजा हमेशा याद रखें कि आजादी के साथ-साथ देश को विभाजन की विभीषिकाएं, दंश, यंत्रणाएं, अलगाव, विस्थापन के हालात भी झेलने पड़े थे।

लाखों मासूम मारे गए, बेघर हुए, सब कुछ लुट गया, लेकिन भारत को स्वतंत्र देखने का जज्बा निराला था, लिहाजा कुर्बानियां भी फूल-सी लगीं। आज हम मणिपुर, नूंह जैसे हालात देखते हैं, तो भीतर से आर्तनाद गूंज उठता है-अरे, हम तो भाई-भाई हैं। इस देश के आजाद नागरिक हैं। एक ही गुलिस्तां के फूल हैं, फिर यह लहू क्यों बहाया जा रहा है? सांप्रदायिक और जातीय दंगे क्यों भड़काए जा रहे हैं? क्यों हत्याएं करने पर हम आमादा हैं? क्या हम अपने ही हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं? इन्हें त्याग दो, भाइयो! यह आजादी बेशकीमती है, कुर्बानियों से मिली है, इसे किसी भी कीमत पर खोया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। देखना होगा कि वह देश के समक्ष क्या विचार रखते हैं। हालांकि देश के कई हिस्सों में बाढ़ से भारी तबाही हो रही है, ऐसे समय में स्वतंत्रता दिवस की खुशी कुछ फीकी लगती है, फिर भी इसे जोश से मनाया जाना चाहिए। जयहिंद।

आजादी को आजादी ही रहने दो

इस वर्ष हम आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह वर्ष बुलंद हौसलों की वो आवाज है जो अंग्रेजी सल्तनत के समय कुचले जाने के कारण भी न दबी, न मरी बल्कि कई जुल्मों को चीरते हुए आज हम तक स्वच्छंद हवा के रूप में हमारी रगों में बह रही है। लेकिन यह हवा आज लगातार जहरीली होती जा रही है। शायद इस हवा में सांस लेने वाले लोग उन लाखों बलिदानियों की शहादत को भूल गए हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना शरीर, अपना परिवार, अपना बचपन, अपनी जवानी और अपनी रुह तक को न्योछावर कर दिया। आखिर क्यों भूल गए हम कि उन बलिदानियों का कर्ज उतारने की जगह हम वर्तमान में ऐसे गूढ़ा कर्ज लेते जा रहे हैं जिसके लिए हमारा भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा।

इस गूंगे समाज में हमारे देश की आजादी के लिए सूनी कोख वाली माताओं से लेकर शब्द तो अभी भी छन-छन कर ही आते हैं। तभी मणिपुर में निर्वस्त्र उन महिलाओं की कराहना के लिए भी हमारे समाज के कान बहरे हो गए। हालांकि मणिपुर तो एक बहाना है, रोज सड़क, चौराहे, यहां तक कि घर की चार दिवारी में लाखों बेटियों की परतंत्रता का भद्दा मजाक बनाया जाता है और यह मजाक आजादी के नाम पर बड़े-बड़े समारोह की शान बनता हुआ अक्सर देखा जाता है। लेकिन हम शांत हैं क्योंकि हमारी खामोशी, हमारी आजादी को मनाने के लिए बहुत जरूरी है। यह मसला किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं। घर से निकलते ही सड़क पर हजारों गाड़ियां इस तरह आजादी मना रही होती हैं कि पैदल चलने वाले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले स्वयं उनसे अपनी आजादी की भीख मांग रहे होते हैं। वहीं सड़क के दोनों तरफ अपनी खुशी को ढूंढने निकले फल, सब्जी व चाय का ठेला लगाने वाले विक्रेता, स्वयं बड़े-बड़े मॉल से प्रतियोगिता करने के लिए आतुर से दिखते हैं। क्योंकि अगर कोई मॉल से निकल कर उन ठेलों से खरीददारी कर लेता है तो वे स्वयं आजादी को अनुभव करने लग जाते हैं। उनकी वही खुशी उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी-कपड़ा-मकान जैसी जरूरतों के लिए मार्ग दिखाती है। **निधि शर्मा**

आदिवासियों की शिक्षा का बदलता स्वरूप

आजादी के अमृत महोत्सव साल में जनजातीय इलाकों में एक उदासीन लोक पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि अब आदिवासियों के स्कूलों की रंगत और रुतबा बदलने के दिन आ गए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की तरह मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बानबे सरकारी स्कूलों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) स्वरूप में संचालित करने के लिए निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय कई मामलों में अहम है।

अनुमान है कि मध्य प्रदेश की तरह देश भर में देर-सबेर पीपीपी स्वरूप में आदिवासियों की शिक्षा का स्वरूप उभरेगा। सवाल है कि क्या यह फैसला भारत की नई शिक्षा नीति का एक क्षेपक है, यानी भविष्य की जनजातीय शिक्षा की कोई रणनीति है? उल्लेखनीय है कि गुजरात और ओड़ीशा में पीपीपी स्वरूप बहुत पहले अपनाया जा चुका है। तो क्या पीपीपी आधारित जनजातीय शिक्षा के एक नए युग की दस्तक है?

पीपीपी स्वरूप का मतलब यह कतई नहीं है कि निजी संस्थाओं को विद्यालय की जमीन, मकान या अन्य किस्म के संसाधनों का मालिकाना हक सौंप दिया जाता है। मुद्दा महज प्रबंधन का भी नहीं, बल्कि सेवाओं के निष्पादन से है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पीपीपी स्वरूप की आड़ में सरकार की विफलताएं परदे के पीछे चली जाती हैं।

ओड़ीशा में ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल, यह स्वरूप कोई विचार नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो जिम्मेदारियों को कम करते हुए एक साधन के रूप में निजीकरण को बढ़ावा देता है। इसमें उम्मीद की जाती है कि विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर शिक्षा के अधिकार को शत-प्रतिशत पूरा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण और वन्य क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर व्यापक निराशा है।

याद किया जा सकता है कि राज्य के झाबुआ जिले में पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में निकली लड़कियों से जुड़ी खबर हाल ही में सुर्खियों में आई थी। विज्ञापनी दावों में यह बार-बार जताने की कोशिश की जाती है कि जनजातियों के विकास के प्रति मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से ईमानदार है, हर साल कल्याणकारी उपायों पर भारी-भरकम राशि खर्च की जाती है। लेकिन नतीजों का हाल जगजाहिर है।

बैकुण्ठपुर पूर्व मण्डी अध्यक्ष ने किया स्थगन आदेश की अवहेलना, कार्यवाही की मांग

नायब तहसीलदार द्वारा दिये स्थगन आदेश को दरकिनार कर वाद भूमि पर किया खेती

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले के ग्राम शिवपुर स्तिथ भूमि खसरा न. 206 में पूर्व मंडी अध्यक्ष जगदीश साहू ने आवेदक बृजलाल साहू की भूमि पर जबरन कब्जा कर खेती करने का मामला सामने आया है। जहां पर आवेदक ने कई बार विरोध दर्ज किया और नही मानने की स्तिथि पर नयाब तहसीलदार खेती करने पर स्थगन आदेश दिया जिस स्थगन को जगदीश साहू द्वारा न मानते हुये न्यायालय के आदेश की आवमानना हुई। जिस पर सुनवाई पश्चात तात्कालीन नायब तहसीलदार भीष्म पटेल ने 19.01.2022 को अपने ऑर्डर शीट में थाना पटना को न्यायलयीन अवमानना की कार्यवाही हेतु आदेशित भी किया गया है जिस पर आज तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो सकी। आवेदक बृजलाल साहू ने बताया कि इस वर्ष भी जगदीश साहू ने जबरन मेरे खेत में धान की रोपाई की है जिस पर 12.8.2023 को शिकायत पत्र के माध्यम से वर्तमान तहसीलदार चांदनी कवंर को पूर्व के अवमानना पर कार्यवाही करने का आवेदन दिया है।

राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के काफी पुराने कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर चुके है और पूर्व में यह मंडी अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर चुके है तथा वर्तमान में कोरिया जिले के साहू समाज के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनयन किये है। आवेदक ने जानकारी देते हुये बताया कि यदि इनके जैसा व्यक्ति को पाटी टीकट देती है तो पार्टी की छवि धूमिल होगी।

यह है मामला

आवेदक बृजलाल साहू निवासी ग्राम शिवपुर ने बताया कि मेरे निजी स्वामित्व की भूमि जिसका खसरा नं. 206 रकबा 0.25 हे0 पर अनावेदक जगदीश प्रसाद साहू ने जबरन बल पूर्वक कब्ज़ा कर धान का रोपा लगा लिया है। जिस पर आवेदक ने बताया कि जबरन कब्जा कर कृषि कार्य करने के संबंध में माननीय नायब तहसीलदार पटना के समक्ष आवेदन पेश किया था जिस पर माननीय न्यायालय ने द्वारा स्थगन आदेश जारी किया था जिसकी जानकारी अनावेदक जगदीश प्रसाद साहू हो होते हुये भी उक्त भूमि पर बल पूर्वक कृषि कार्य कर लिया है तथा न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना किया है। आवेदक ने यह भी बताया कि जगदीश प्रसाद साहू चालाक किस्म का व्यक्ति है जो सत्यता को छुपाते हुये माननीय न्यायालय को गुमराह में रखा है और अवैधानिक तरीके से आवेदक के भूमि को हड़पना चाहता है। जिस पर आवेदक ने तहसीलदार से निवेदन किया है कि अनावेदक के विरूद्ध न्यायालिन अवमानना की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे और मेरे स्वामित्व की भूमि जगदीश प्रसाद साहू से मुक्त करा कर मुझे कब्जा दिलाया जाये।

नए सीईओ की पदस्थापना के बाद जनपद पंचायत की व्यवस्था चरमराई

प्रतापपुर। एक तरफ जहां शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ रखने प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं वहीं दूसरी ओर अधिकारी हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हैं।

यहां बात कर रहे हैं जनपद पंचायत प्रतापपुर की जहां नए सीईओ पारस राम पैकरा की पदस्थापना के बाद से ही पंचायतों में अव्यवस्थाओं का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि लगभग तीन माह से जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत डांड़करवां, गोरगी व धूमाडांड़ इन तीनों पंचायतों की जिम्मेदारी अकेले संभाल रहे सचिव अनिल गुप्ता को तो जिला पंचायत कार्यालय में संलग्न कर दिया गया पर अभी तक इन तीनों ही पंचायतों में जनपद पंचायत सीईओ ने नए सचिव की पदस्थापना नहीं की है

जिसके कारण तीनों पंचायतें सचिव रहित हो गई हैं। पंचायतों के सचिव रहित हो जाने से विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा पंचायतों के खातों में भेजे गई राशि पंचायतों के खातों में ही अटकी पड़ी है। इस संबंध में तीनों ही पंचायतों के सरपंचों का कहना है कि सचिव के हस्ताक्षर के बगैर वे पंचायतों के खातों से राशि नहीं निकाल पा रहे जिसके कारण पंचायतों के विकास कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। ऊपर से ग्रामीण भी सचिव के न रहने से अपने छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बताया जा रहा है कि सचिव अनिल गुप्ता को जिला पंचायत में संलग्न किए जाने के बाद भी वे अधिकारियों की मेहरबानी से जिले में न जाकर उक्त तीनों पंचायतों में ही यथावत बने हुए हैं पर पंचायतों का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ऊपर से आश्चर्य का विषय तो यह है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष जगत लाल आयम द्वारा उक्त मामले की जानकारी जनपद पंचायत सीईओ पारस राम पैकरा को देने के बाद भी वे मौन बने हुए हैं।

एक अन्य पंचायत में भी यही स्थिति

जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चाचीडांड़ भी सचिव रहित बनी हुई है। बता दें कि यहां के सचिव के ऊपर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए अनियमितताओं के आरोप के बाद तत्कालीन सीईओ मो निजामुद्दीन ने उसे हटाते हुए उसके स्थान पर एक नए सचिव को पदस्थ किया था पर उक्त सचिव है कि नए सचिव को प्रभार देने का नाम नहीं ले रहा है जिसके कारण इस पंचायत के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं साथ ही कई ग्रामीणों को मिल रही पेंशन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

1 करोड़ की राशि से चौपाटी में मॉड्युलर गुमटियों का होगा निर्माण

अंबिकापुर। चौपाटी को बेहतर बनाने के लिए जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के व्यक्तिगत प्रयास से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 1 करोड़ रुपय की राशि नगर पालिक निगम को इस कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के प्रयास पर उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 1 करोड़ रुपय इस कार्य हेतु उपलध कराया है। चौपाटी में कार्यों को प्रारंभ करने एवं उसकी कार्ययोजना बनाने के लिए सोमवार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव एवं महापौर डॉ. अजय तिर्की ने चौपाटी का दौरा किया। इस पूरे काम को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए नगर निगम तत्पर है। इस दौरान विवेक सिंह, शुभम जायसवाल, मिथुन सिंह सहित नगर निगम का अमला भी वहां पर मौजूद था।

शासन के निर्देश के बाद भी समय पर नहीं आते अधिकारी एवं कर्मचारी

खड़गवां। राज्य शासन ने निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5.30 तक आम जनता के लिए खुल रहें हैं। तथा हफ्ते में दो दिन छुट्टी घोषित की गई है । शासन के इस आदेश का उल्लंघन खड़गवां विकास खंड के कार्यालयो में देखा जा सकता है। शासन के आदेश के परिपेक्ष में खड़गवां के कार्यालयों में इसकी पड़ताल की गई । जिसमें कई कार्यालयो मे अधिकारी कर्मचारी नहीं आए थे। यहां पर लगभग पदस्थ अधिकारी कर्मचारी का यही हाल है मुख्यालय के कार्यालय में कभी भी समय पर नहीं आते है कार्यालय का जदातर संचालन पदस्थ कर्मचारीओ के द्रारा ही करते देखा जा सकता है।

गौरतलब है की खड़गवां के कार्यालय में राज्य शासन के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में लापरवाही और मनमानी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी और कौन कार्यवाही करेगा या सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रशासनिक अधिकारियों कि लापरवाही का ढर्रा इसी तरह चलता रहेगा या कलेक्टर महोदय इस पर लगाम लगाएंगे ?

पंचायत राशि गबन मामले में कार्यवाही तथा राशि वसूली को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

लखनपुर। पंचायत राशि गबन करने के मामले में गणेशपुर के ग्रामीणों ने 23 अगस्त दिन बुधवार को तहसील कार्यालय पहुंचे एसडीएम बी आर खांडे को ज्ञापन सौप पंचायत के राशि 1135000 की वसूली तथा सरपंच सचिव के खिलाफ की कार्यवाही को लेकर मांग की है। 15 दिवस के भीतर सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने ग्रामीणों के द्वारा उग्र आंदोलन का चक्का जाम किया जाएगा। पूरा मामला लखनपुर विकासखंड के ग्राम गणेशपुर का है जहां सरपंच सचिवों के कागजों में निर्माण कार्य कर राशि पंचायत राशि का बंदरबाट किया गया था। परंतु धरातल पर निर्माण कार्य नहीं हुआ था ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगने पर इसकी शिकायत जन चौपाल में सरगुजा कलेक्टर से की थी। और जांच करने अधिकारी ग्राम गणेशपुर पहुंची जांच उपरान्त 1135000 राशि वसूली अग्रिम कार्रवाई हेतू एसडीएम कार्यालय को जांच प्रतिवेदन भेजा गया था। परंतु आज दिनांक तक राशि की वसूली नहीं होना था सरपंच सरसों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंच एसडीएम को ज्ञापन सौंप सरपंच सचिव के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ग्राम पंचायत गणेशपुर शिकायत पर सरपंच- सचिव के खिलाफ 14 वा 15 वा वि ?ा योजना तथा विभिन्न मदो की राशि गमन करने के आरोप सिद्ध पाए गए हैं। जिस पर जांच रिपोर्ट पर सरपंच सचिव के खिलाफ 11 लाख 35 हजार रुपए वसूली करना पाया तथा कार्यालय

जनपद पंचायत लखनपुर द्वारा जांच रिपोर्ट अनविभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर को दिनांक 30 /12/ 2022 जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। परंतु आज भी पंचायत में सचिन यथावत अतिरिक्त प्रभार पर है वहीं सरपंच की भी अनियमिता लगातार की जाने की शिकायत बार-बार मिल रही है।

लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत कई ग्राम पंचायत हैं ऐसे है जिसमें सरपंच सचिव के द्वारा मिली भगत कर जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि को मनमानी तोर बिना कार्य किए आहरण करने का मामला हमेशा ही सुर्खियों में रहा है इस तारतम में लखनपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशपुर में विगत वर्ष पूर्व ग्राम वासियों द्वारा कलेक्टर सरगुजा को जन चौपाल के माध्यम से जिसका टोकन क्रमांक 20 20 32 22002217 के द्वारा ग्राम पंचायत गणेशपुर के द्वारा फर्जी तरीके से कागजों में निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में जांच हेतु शिकायत प्राप्त हुआ था जिसका स्थल पर जाकर जांच अनुभाग्य अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा लखनपुर एवं समाज शिक्षा संगठन लखनपुर के द्वारा किया गया अनुभाग्य अधिकारी के द्वारा शिकायत एवं आहरित राशि के आधार पर निर्माण कार्यों का सत्यापन किया गया जो जिसमें अनियमित पाई गई है ।

जिसका मुख्य रूप से सरपंच सचिव के द्वारा 14 वा 15 में वा वित्त योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है।

ग्राम पंचायत गणेशपुर में निर्मित ग्राम सभा की बैठक नहीं की जाती है और ना ही ग्राम पंचायत के पंचों को बैठक की सूचना दी जाती है यह शिकायत भी सही पाया गया है।

ग्राम पंचायत में प्रभारी पंचायत सचिव केशवर सिंह नियमित रूप से ग्राम पंचायत उपस्थित नहीं होते हैं और ना ही नियमित रूप से ग्राम पंचायत का कार्यालय खुलता है सरपंच श्रीमती फूल कुमारी कोरवा ग्राम पंचायत में नियमि ?ा नही रहते हैऔर ग्राम पंचायत पुहपुटरा में निवास करती है जिसके कारण ग्राम पंचायत का कार्य प्रभावित होता है यह भी सही पाया गया है।

वहीं सरपंच सचिव द्वारा 14वां वित्त एवं 15 वा वित्त की राशि मनमानी तरीके से आहरण कर राशि को गमन कर लिया गया है।

वहीं जांच में अनुभागीय अधिकारी ग्रामीण आंतरिक की सेवा लखनपुर के द्वारा जांच किया गया जिसमें निर्माण कार्य नहीं कराया पाया गया है जिस पर निर्माण कार्य नहीं होने की स्थिति में 11 लाख 35 हजार रुपए सरपंच सचिव से वसूली किया जाना पाया गया है।

उक्त जांच रिपोर्ट जनपद कार्यालय द्वारा अनुभागिय अधिकारी राजस्व को 30 दिसंबर 2022 को ही प्रस्तुत किया गया था परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही सरपंच सचिव के खिलाफ नहीं हो पाई है। ना ही रिकवरी की राशि 11 लाख 35 हजार वसूली का कोई पत्र भेजा गया है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का भी मौन स्वीकृति मिला है। इसके संरक्षण से आज भी सचिन यथावत अतिरिक्त प्रभार में ग्राम पंचायत गणेशपुर में बना हुआ है।

इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बि आर खांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच प्रतिवेदन आया है। सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में सचिव से जानकारी लेकर अग्रिम कार्रवाई हेतू सरगुजा कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया जाएगा।

निर्माण एजेंसी की मनमानी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सीसी सड़क

- **महज 2 माह में ही उखड़ने लगी सड़क**
- **ग्रामीणों का आरोप घटिया सामग्री का किया गया उपयोग**

खड़गवां। खड़गवां जनपद पंचायत से महज चंद किलोमीटर मीटर की दूरी एवं मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत दुबछोला मेन रोड से संरपच मुहल्ला तक सी सी सडक निर्माण कार्य कराया गया है इस सी सी सड़क निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सी सी सड़क का निर्माण कार्य घटिया सामग्री का उपयोग कर सी सी सड़क निर्माण कार्य किया गया है इस निमार्ण कार्य में घटिया सीमेंट गुणवत्ता विहीन गिट्टी एवं जिस साइज की गिट्टी का उपयोग कर सी सी सड़क का निर्माण कार्य किया जाना था वो नहीं किया गया है इस सी सी सड़क के निर्माण कार्य के नीचली सतह पर मुरम बिछाकर रोड रोलर चला कर सी सी सडक का निर्माण कार्य करना था जो नहीं किया गया है और जिस गुणव ?ाा युक्त प्लास्टिक उपयोग कर सी सी सड़क का निमार्ण बाईब्रेटर मशीन के बिना सी सी सड़क के निमार्ण कार्य किया गया था जिसके कारण ये सी सी सडक महज एक से दो माह में धराशाही हो गई जगह जगह सड़क उखड गई। इस निर्माण स्थल पर ब्राईब्रेटर मशीन सिर्फ और सिर्फ वो पीस के तौर पर रखी रहती थी अगर किसी अधिकारी दौरा या निरीक्षण हो गया तो उस मशीन को सिर्फ देखने के लिए सिर्फ चालू किया जाता है। उसका कही इस्तेमाल नहीं किया गया है सी सी सड़क निर्माण कार्य की नीचली सतह पर जिस समाग्री का उपयोग कर सतह को तैयार कर सी सी सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना था वो नहीं किया गया है और आनन फानन में गुणवत्ता विहीन गिट्टी सीमेंट प्लास्टिक का उपयोग कर सी सी सड़क को तैयार कर दिया गया है। जब सी सी सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था उस समय निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का कोई सूचना पटल नहीं लगाया गया था और सी सी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया था इस सी सी सड़क पर सूचना पटल नहीं होने से स्थानीय ग्रामीणों को किस योजना से एवं कितनी लागत से एवं किस मजदूरी दर पर कार्य कराया गया है किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत अपनी मनमानी से सी सी सड़क का निर्माण कार्य कराया था।

मिट्टी भरकर किया गया सड़क निर्माण

जब सी सी सडक निर्माण कार्य के पश्चात चंद दिनों में उखड़ ने लगी उसके बाद ही सूचना पटल लगाया गया है दुबछोला ग्राम पंचायत मे सी सी सडक निर्माण कार्य की स्वीकृत राशि छ: लाख रूपये की लागत से सी सी सडक का निर्माण कार्य कराया गया था। सी सी सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है वहां एक से डेढ़ फीट के गड्ढ़ा था जहां पर सिर्फ मिट्टी भरकर लाखों रुपए लागत की सड़क का निर्माण कार्य करा दिया गया है। यह लाखों रुपए की लागत की सी सी सडक महज एक से दो माह में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है।

क्या कहतें है अधिकारी

इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से जानकारी चाही तो उन्होंने ने कहा कि हमारे द्वारा सी सी सडक निर्माण कार्य की राशि का भुगतान रोक दिया है जष तक सी सी सडक निर्माण कार्य सही तरीके से गुणवत्ताा युक्त नहीं बन जाती राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

थूक पालिश कर किया गया सड़क निर्माण

जबकि इस सी सी सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण ग्रामीण यांत्रिकी विभाग खड़गवां के अनुविभागीय विभागिय अधिकारी के द्वारा निमार्ण स्थल का भी निरीक्षण करना होता है जो ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा खड़गवां कार्यालय मैं बैठकर निर्माण कार्य का निरीक्षण कर लिया गया और यह सी सी सडक जब एक माह के अंदर उखड़ने लगी तो सी सी सडक निर्माण कार्य का भुगतान रोक कर पुन: सी सी सडक निर्माण कार्य कराने का अनुविभागीय अधिकारी ने कहा और सी सी सडक निर्माण कार्य पुन: भी थूक पालिश में निर्माण कार्य करा दिया गया है जो अभी भी जगह जगह पर उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

मिलेट्स कैफे के होम डिलेवरी एक्सप्रेस का हुआ शुभारम्भ

बैकुंठपुर। कलेक्टरेट परिसर में कोरबा लोकसभा के सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ महतारी की भव्य प्रतिमा का अनावरण के पश्चात कलेक्टर परिसर में स्थापित 'कोरिया मिलेट्स कैफे' द्वारा शुरू की जा रही 'होम डिलेवरी एक्सप्रेस' का भी श्रीमती महंत ने शुभारम्भ किया।

शुभारम्भ के दौरान श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत ने कहा कि जब भी स्कूटी, बाइक से होम डिलेवरी करें तो हेलमेट पहनकर व सावधानी के साथ वाहन चलाने की अपील भी की। श्रीमती महंत ने कैफे में जाकर कोदो से बने खीर, उपमा, रागी से बने चीला व ज्वांर से बने गुलाब जामुन का स्वाद लिया। श्रीमती महंत ने कहा कि सचमुच में मिलेट्स भोजन, नाश्ता सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। वहां बड़ी संख्या में उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों-कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि मिलेट्स का नाश्ता और भोजन जरूर करें। 'होम डिलेवरी एक्सप्रेस' के शुभारम्भ अवसर पर संसदीय सचिव एवं कोरिया विधायक अम्बिका सिंहदेव, कोरिया जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदान्ती तिवारी, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी नगर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि प्रतीक गुप्ता, योगेश शुक्ला, नजीर अहमद, अशोक जायसवाल, अनिल जायसवाल, अन्नपूर्णा सिंह, संगीता राजवाड़े, चन्द्रप्रकाश राजवाड़े, विनोद शर्मा, एसडीएम अंकिता सोम, डिप्टी कलेक्टर राकेश कुमार साहू, विनय कुमार कश्यप सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।

खबरों से रहें अपडेट
www.scgnews.in
SCG News

प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
श्रीमान,सियंबर सिंह जी,
सरपंच
ग्राम पंचायत राजापुर,
जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़
विनीत, समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत
राजापुर सूरजपुर

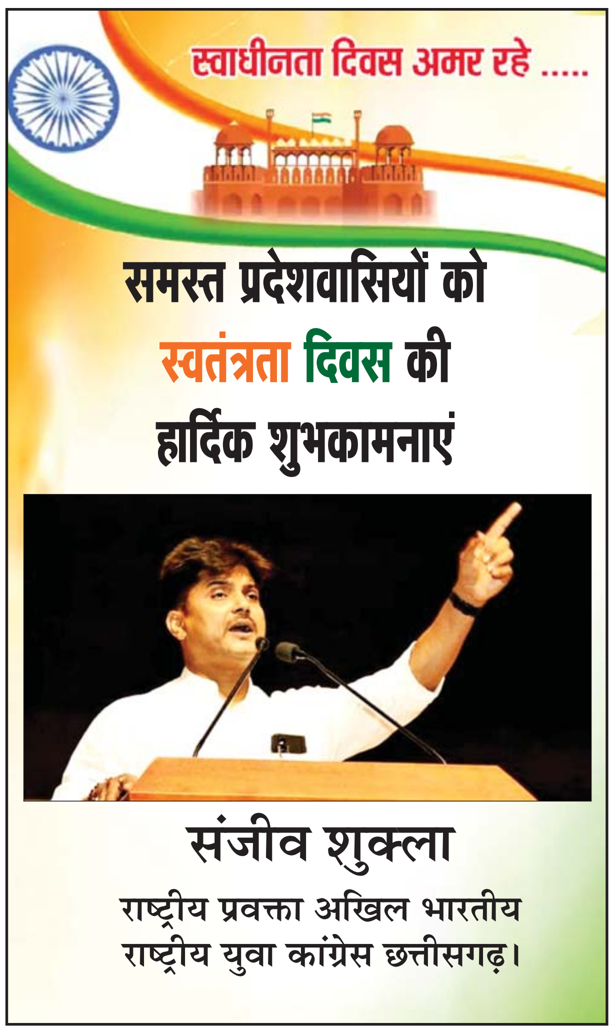

स्वाधीनता दिवस अमर रहे .....
समस्त प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं
संजीव शुक्ला
राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय
राष्ट्रीय युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़।

राजकुमारी सिंह मरावी
जिला पंचायत अध्यक्ष, सूरजपुर
समस्त प्रदेशवासियों
को स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनायें
शिव भजन सिंह मरावी
प्रदेश आदिवासी कांग्रेस कमेटी महामंत्री
जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष
बलरामपुर आदिवासी कांग्रेस प्रभारी

77वं
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
स्वतंत्रता दिवस,
रक्षाबंधन, जन्माष्टमी कि
आप सभी प्रदेशवासियों
को हार्दिक बधाई एवं
अशेष शुभकामनाएं।।
भागवत पैकरा
सरपंच
ग्राम पंचायत सोनपुर तहसील
रामानुजनगर जिला सूरजपुर
छत्तीसगढ़
विनीत, समस्त ग्रामपंचायतवासी सोनपुर रामानुजनगर
जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।।

स्वतंत्रता दिवस
15TH
AUGUST
स्वतंत्रता दिवस,
रक्षाबंधन, जन्माष्टमी कि
आप सभी प्रदेशवासियों
को हार्दिक बधाई एवं
अशेष शुभकामनाएं।।
यशवंत तुषार साहू
किसान नेता
महासमुंद विधानसभा
छत्तीसगढ़

15 August
समस्त देशवासियों को
आज़ादी के महापर्व
स्वतंत्रता
दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
विकास उपाध्याय

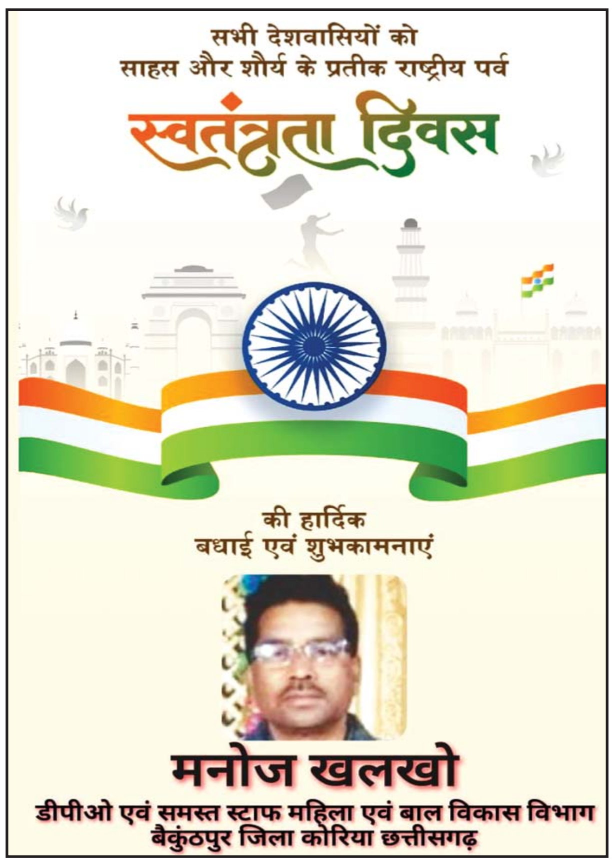

सभी देशवासियों को
साहस और शौर्य के प्रतीक राष्ट्रीय पर्व
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं
मनोज खलखो
डीपीओ एवं समस्त स्टाफ महिला एवं बाल विकास विभाग
बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़

सूरजपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक मात्र हॉस्पिटल
PRA अस्पताल
SRPR
साधुराम प्रहलाद राय
मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे
आपातकालीन सुविधा
CT स्केन
कलर सोनोग्राफी
डिजिटल एक्स–रे
पैथोलॉजी संबंधित जॉच
ECHO
24x7 दवाई दुकान
24x7 एम्बुलेंस
24x7 चौबीस घण्टे सम्पूर्ण सुविधाओं के साथ
आपकी सेवा मे सदैव तत्पर
care apno jaisi
PRA परिसर, श्याम मंदिर गली, पार्वती घाट के बगल में, सूरजपुर
98261 94545, 98262 94545

सभी देशवासियों को
साहस और शौर्य के प्रतीक राष्ट्रीय पर्व
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं
ललित शुक्ला
सहायक आयुक्त एवं समस्त स्टाफ
बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़

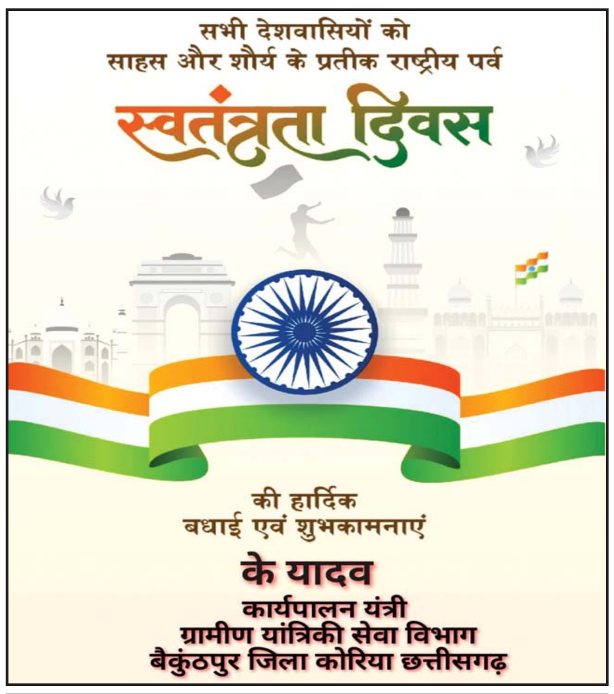

सभी देशवासियों को
साहस और शौर्य के प्रतीक राष्ट्रीय पर्व
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं
के यादव
कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग
बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़

स्वतंत्रता दिवस पर
श्रमिकों के हित में
महत्तवपूर्ण घोषणा
अंशकालीन सफाई कर्मी भाई-बहनों
एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े
रसोईयों के मानदेय में 500 रुपए
प्रतिमाह वृद्धि की घोषणा हुई
सुशील सन्नी अग्रवाल

आप सभी को
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं!
शफी अहमद
अध्यक्ष श्रम कल्याण मण्डल छ:ग शासन

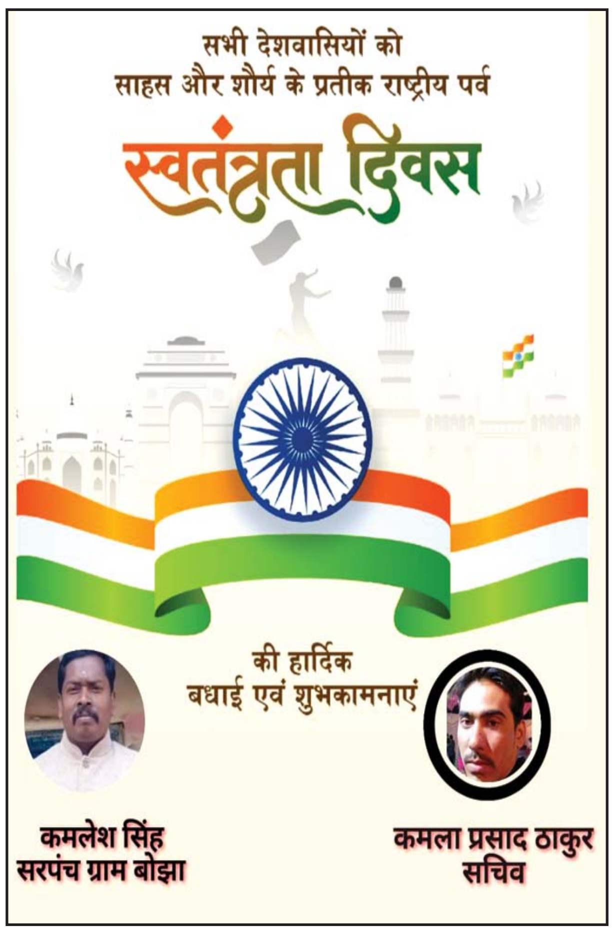

सभी देशवासियों को
साहस और शौर्य के प्रतीक राष्ट्रीय पर्व
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं
कमलेश सिंह
सरपंच ग्राम बोझा
कमला प्रसाद ठाकुर
सचिव

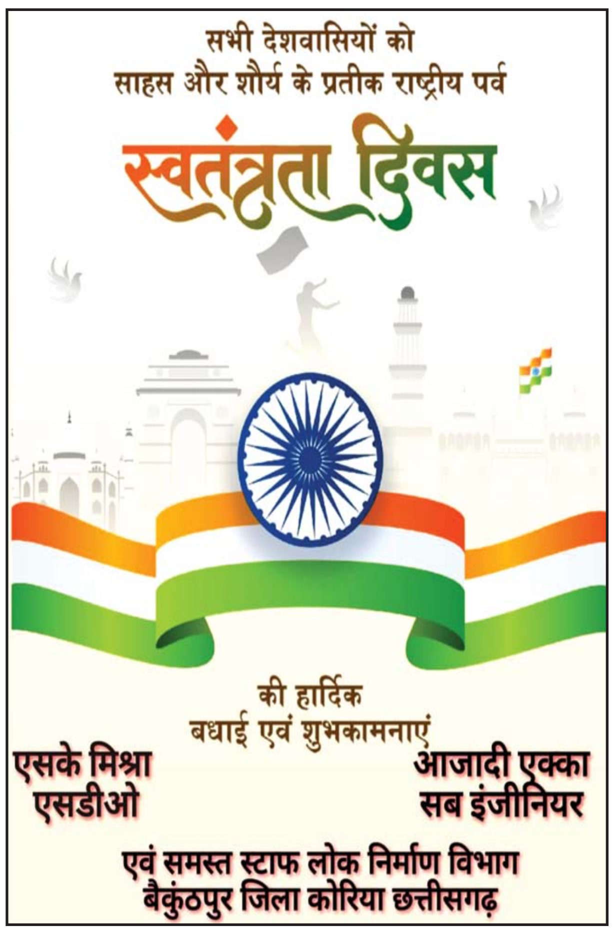

सभी देशवासियों को
साहस और शौर्य के प्रतीक राष्ट्रीय पर्व
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं
एसके मिश्रा
एसडीओ
आजादी एक्का
सब इंजीनियर
एवं समस्त स्टाफ लोक निर्माण विभाग
बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़

विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी,
गणेशोत्सव की हार्दिक बधाई
कांती देवी
सरपंच
ग्राम मानी, जनपद पंचायत प्रतापपुर
जिला सूरजपुर (छग)

आप सभी देशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन,
जन्माष्टमी, गणेशोत्सव की हार्दिक बधाई
रामलखन सिंह
सरपंच
ग्राम पंचायत कुप्पी,
जनपद पंचायत ओड़गी,
जिला सूरजपुर (छग)

नायब तहसीलदार भी अब कहलाएंगे राजपत्रित अधिकारी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय सम्मेलन में की घोषणा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित पद का दर्जा दे दिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा 'कृषि एवं प्रदेश के किसानों के विकास में राजस्व विभाग का योगदान' थीम पर आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में भुइंया के मितान स्मारिका का भी विमोचन किया। सम्मेलन में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की प्रमोशन संबंधी मांग पर मुख्यमंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि अधिकारियों का समय पर प्रमोशन जरूर होगा।

मुख्यमंत्री ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के जिम्मेदारियों की बात करते हुए कहा कि आप सभी प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं और आपको बहुत सारे विविधतापूर्ण कार्य करने होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व अधिकारियों ने कोविड आपदा के समय महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने और लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया था जिसकी वजह से पूरे देश में छत्तीसगढ़ की सराहना हुई।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना किसी शिकायत के पूरे प्रदेश में डेढ़ लाख एकड़ भूमि गौठानों के लिए आरक्षित की गई। यह काम कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के कार्य के प्रति समर्पण को दिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में कसावट और जनता की सेवा करने के जज्बे की वजह से आज सुकमा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण और बंटवारा प्रमाण पत्र लोगों को उनके घर जाकर दिया जा रहा है।

सम्मेलन में राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने नए तहसीलों और अनुविभाग की मांग की जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा किया। आम लोगों को सहूलियत हो और सरकार लोगों तक पहुंचे इसके लिए नए जिलों की स्थापना की गयी है।

मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे देश में सिर्फ तहलीदार ही एक ऐसा पद है जो भारत ही नहीं बल्कि अन्य पड़ोसी देशों में भी इसी नाम से जाना जाता है। अतः जितना बड़ा इस पद का नाम है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है जिसे अच्छी तरह से निभाना आप सभी की जिम्मेदारी है।

राज्य स्तरीय प्रांतीय सम्मेलन में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की तरफ से प्रांताध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार लहरे, सचिव श्री विक्रांत सिंह राठौर, प्रवक्ता श्री शशिभूषण सोनी समेत राज्य भर से आए तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष होंगे मंत्री अकबर

रायपुर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे की सहमति के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनमें चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के रुप में मंत्री मोहम्मद अकबर को नियुक्ति किया है। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. शिव कुमार डहरिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के अध्यक्ष धनेन्द्र साहू व योजना एवं रणनीति समिति के अध्यक्ष होंगे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू।

चुनाव घोषणा पत्र समिति में अध्यक्ष मो. अकबर, रवीन्द्र चौबे, डॉ. शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, धनेन्द्र साहू, श्रीमती फूलो देवी नेताम, शैलेश पांडे, अरुण वोरा, शिशुपाल सोरी, द्वारिकाधीश यादव, कुँवर सिंह निषाद, राजेश तिवारी, चुन्नी लाल साहू, इदरीश गांधी, हेमा देशमुख, अटल श्रीवास्तव, अजय तिर्की, राजेंदर जग्गी, वाणी राव, श्रीमती शेषराज हरबंस, आकाश शर्मा।

चुनाव प्रबंधन समिति में अध्यक्ष डॉ. शिव कुमार डहरिया, रामगोपाल अग्रवाल, अरूण सिंघानिया, राजेश तिवारी, गिरीश देवांगन, मलकियत सिंह गैदु, गजराज पगारिया.

छत्तीसगढ़ में 12वीं के साथ ही आईटीआई प्रशिक्षण शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को रोजगार मिला रहा है। राज्य शासन की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कई योजना निकाल रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के युवा अब 12वीं के पढ़ाई के साथ आटीआई में अपनी मनपसंद ट्रेड में प्रशिक्षण ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश के युवाओं के लिए कई योजनाएं ला रही है। इससे विद्यार्थी युवा वर्ग बेरोजगार सभी लाभांवित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के प्रयास कर रहा है। बेहतर शिक्षा के साथ उनका कौशल उन्नयन किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से सकारात्मक बाते बताया जा रहा है। युवा अपने लोक संस्कृति पारंपरिक खेलों के प्रति आकर्षित हो रहे है। इसके लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। युवाओं का आर्थिक सहायता के लिए प्रतियोगी परीक्षा पीएससी और व्यापम की परीक्षा शुल्क माफ कर दी है। कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिला है।

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के युवाओं के लिए कक्षा 12 वीं के साथ आईटीआई की सुविधा दे रही है। राज्य के युवाओं बेहतर शिक्षा के साथ उनका कौशल उन्नयन कर रोजगार से जोड़ना प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से वर्ष 2018 से लेकर 30 जून 2023 की स्थिति में 43 हजार 862 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इसमें से 13 हजार 661 युवाओं को रोजगार उपलब्ध हुआ। 10 हजार 254 युवाओं ने स्व-रोजगार प्राप्त किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 15 हजार प्रशिक्षित युवाओं में से 3854 को रोजगार मिला है।

राज्य के कई 12वीं तक पढ़ कर छोड़ देते हैं इसके बाद ऐसे युवा बेरोजगार बने रहते हैं। 12 वीं कक्षा से ही आईटीआई व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र जो साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के इच्छुक हैं। उनके लिए स्कूलों और आईटीआई समन्वय के माध्यम से उन्हें स्कूली शिक्षा और अपनी रुचि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है।

भाजपा के 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी

रायपुर। भाजपा ने आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। जिसमें कांकेर से आशाराम नेताम, प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी और कोरबा से लखनलाल देवांगन को उम्मीदवार बनाया गया है। पहली सूची में भाजपा ने दस अनुसूचित जनजाति और एक एससी के अलावा सांसद विजय बघेल पर भरोसा जताया है। सांसद विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं और उन्हें पाटन सीट से उतारा गया है। इसी सीट से सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव जीता था। ऐसे में इस सीट पर चुनाव चाचा बनाम भतीजा होग। सूची में पांच महिलाएं भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में महज ढाई महीने ही शेष बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ पर लगातार फोकस किए हुए हैं। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। दोनों दलों के नेता पूरी तरह से चुनावी समर में कूद चुके हैं। इस क्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 20 अगस्त को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अगस्त, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सितंबर और केसी वेणुगोपाल 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे।

गुरुवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। हालांकि चर्चा ये भी है कि करीब आधी सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। फिलहाल, बीजेपी ने 21 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

दूसरी ओर रामानुजगंज से पूर्व सांसद रामविचार नेताम को टिकट दिया गया है। आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में आए ओपी चौधरी का खरसिया से टिकट काटकर महेश साहू को मौका दिया गया है। ऐसे में उनके भविष्य पर खतरा मंड़रा रहा है। हालांकि चर्चा है कि चंद्रपुर से उन्हें टिकट मिल सकता है।

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र	उम्मीदवार
1.	प्रेमनगर (4)	भूलन सिंह मरावी
2.	भटगांव (5)	लक्ष्मी राजवाड़े
3.	प्रतापपुर (अजजा) (6)	शकुंतला सिंह पोर्थे
4.	रामानुजगंज (अजजा) (7)	रामविचार नेताम
5.	लुन्द्र (अजजा) (9)	प्रबोज भींज
6.	खरसिया (18)	महेश साहू
7.	धर्मजागढ़ (अजजा) (19)	हरिश्चन्द्र राठिया
8	कोरबा (21)	लखनलाल देवांगन
9.	मरवाही (अजजा) (24)	प्रणव कुमार मरपच्ची
10.	सरायपाली (अजा) (39)	सरला कोसरिया
11.	खल्लारी (41)	अलका चंद्राकर
12.	अभानपुर (53)	इन्द्रकुमार साहू
13.	राजिम (54)	रोहित साहू
14.	सिहावा (अजजा) (56)	श्रवण मरकाम
15.	दौंडी लोहारा (अजजा) (60)	देवलाल हलवा ठाकुर
16.	पाटन (62)	विजय बघेल, सांसद
17.	खैरागढ़ (73)	विक्रांत सिंह
18.	खुज्जी (77)	गीता घासी साहू
19.	मोहला मानपुर (अजजा) (78)	संजीव साहा
20	कांकेर (अजजा) (81)	आशाराम नेताम
21.	बस्तर (अजजा) (85)	मनिराम कश्यप

21 सीटों पर जातिगत फैक्टर

बीजेपी ने जो 21 सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। उसमें जातिगत समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। इसी के आधार पर टिकट दिया है। एसटी, एससी और ओबीसी सीट का ध्यान रखकर टिकट दिया गया है। 21 सीटों में 9 सीटें अजा/अजजा के लिए रिजर्व है। 10 सीटों पर ST और 1 सीट पर SC, एक सामान्य सीट पर आदिवासी चेहरे को मौका दिया गया है। जिन 21 सीटों पर भाजपा दिकट दिए हैं। वहां अधिकांश पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। कई ऐसी सीटें हैं, जहां बीजेपी कम ही जीत पाई है। बीजेपी ने पिछली बार इन सीटों जिन्हें मौका दिया था, लगभग सभी जगहों पर बदल दिया गया है।

बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने पर सीएम भूपेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लिस्ट में कुछ खास नहीं है। वहीं प्रत्याशी बनाए पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि बीजेपी ने उन्हें पाटन से मौका दिया है। जनता के आशीर्वाद से भूपेश को पटखनी देंगे। हालांकि कौन, किसको मात देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।

कमजोर सीटों पर फोकस

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर है, वहां पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं, इस बार जाति समीकरण को भी प्राथमिकता देकर लिस्ट जारी की गई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पहली सूची जल्दी जारी की गई है। ऐसे में भरपूर समय मिलने से पार्टी को चुनाव के पक्ष में माहौल बनाने का समय मिल गया है।

उम्मीदवारों को चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश

उम्मीदवारों को चुनावी तैयारियों में जुट जाने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं आयकर, पारिवारिक संपत्ति विवरण, अपराधिक केस की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण पत्र आदि एकत्र करने के लिए कहा गया है। जिससे दस्तावेज पुख्ता रहे और नामांकन पत्र रद्द करने की नौबत न आए।

सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शनिवार को होने वाले कांग्रेस की दो बड़ी बैठक पूरी हो चुकी है। अभा कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल राजीव भवन में कांग्रेस की दो बड़ी बैठकें ली। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक व लोकसभा के पर्यवेक्षकों से चुनावी तैयारी की रिपोर्ट पर बैठक आयोजित की गई। वहीं कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का दौरा भी तय हो गया है। 2 सितंबर को राहुल गांधी रायपुर दौरे पर आएंगे। सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। 4 सितंबर तक पैनल सूची सेंट्रस इलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, पालिटिकल अफेयर कमेटी की अध्यक्ष कुमारी सैलजा, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में हुई बैठक में चुनावी तैयारियों पर मंथन किया गया।

करीब साढ़े तीन घंटे चली बैठक में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है 75 सीट। छत्तीसगढ़ में हमारे इस टारगेट को लेकर हमने चिंतन किया, प्लान किया, हम जीतेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी कहा कि हर रिपोर्ट में हमें 75 प्लस सीटें मिल रही है। भले ही रिपोर्ट विपक्ष की हो और वह छिपा रहे हों। सैलजा ने बताया कि दो सितंबर को राहुल गांधी तो आठ सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का दौरा है। टिकट वितरण को लेकर सैलजा ने कहा कि ब्लाक स्तर पर दावेदारों का आवेदन लिया जा रहा है। 31 अगस्त तक जिला कांग्रेस कमेटी नामों का पैनल पीसीसी को देगी। तीन सितंबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। चार सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, यहां से रिकमेंडेशन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज देंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में पहली लिस्ट जारी की जाएगी।

सात समितियों से कांग्रेस साधेगी सत्ता

इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने एक साथ सभी चुनावी कमेटियों की घोषणा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को चार कमेटियों की घोषणा की। इससे पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता वाली पालिटिकल अफेयर कमेटी की घोषणा गुरुवार देर रात की हुई थी। इससे पहले प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष दीपक बैज और स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष अजय माकन को बनाया गया था। कांग्रेस सात चुनावी कमेटियों की घोषणा के साथ ही सत्ता को साधने के मोर्चे पर उतर गई है। कांग्रेस की चुनावी समितियों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए अलग-अलग कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए हैं। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची आने के अगले दिन कांग्रेस ने सभी चुनावी कमेटियों की घोषणा करके चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है।

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति के हाथों मिला भूमि सम्मान

भूमि प्रबंधन के लिए देश के शीर्ष जिलों में बेमेतरा और सरगुजा ने बनाई जगह

रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही प्रदेश के दो जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के मौजूदा चार घटकों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रदेश और दो जिलों को यह सम्मान मिला है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश को भूमि प्रबंधन के लिए सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने प्रदेश के राजस्व विभाग और सरगुजा तथा बेमेतरा जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीआईएलआरएमपी अंतर्गत प्रदेश में बेहतर काम हुए हैं। भूमि संबंधी जानकारियां आम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रही है। जमीन से जुड़ी जानकारियां ऑनलाईन मौजूद है और बरसों पुराने महत्वपूर्ण दस्तावेजों का व्यवस्थित संधारण करने का काम किया गया है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राज्य स्तर पर भू-अभिलेखों के डिजिटाईजेशन और प्रबंधन के लिए सचिव राजस्व विभाग श्री नीलम नामदेव एक्का, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक श्रीमती किरण कौशल, संचालक भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा ने राष्ट्रपति के हाथों भूमि सम्मान प्राप्त किया। इसी प्रकार जिला स्तर पर भू-अभिलेखों के डिजिटाईजेशन और प्रबंधन के लिए बेमेतरा कलेक्टर श्री पीएस एल्मा और सरगुजा कलेक्टर श्री कुंदन कुमार को भी भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) अंतर्गत प्रदेश में भूमि प्रबंधन से जुड़े 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह भूमि प्रबंधन से जुड़े चार घटकों लैण्ड रिकार्ड का डिजिटाइजेशन, पंजीयन कार्यालय का तहसील कार्यालय से समन्वय, मॉर्डन रिकार्ड रूम तथा सर्वे-रिसर्वे का कार्य प्रदेश के सरगुजा और बेमेतरा जिले में शतप्रतिशत पूर्ण हो चुका हैं। ये जिले भूमि प्रबंधन में देश के शीर्ष जिलों में शामिल हैं।

भाजपा के हुए विधायक धर्मजीत सिंह

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी से मुंगेली जिले के लोरमी से वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान रिटायर्ड आईएफएस एसएसडी बड़गैया और धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी ने भी बीजेपी का दामन थामा लिए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।

इस मौके पर विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े दल बीजेपी में शामिल होना मेरे लिए बेहद गौरव का पल है। 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के रायपुर में रैली के दौरान ही इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि धर्मजीत सिंह बीजेपी ज्वॉइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं विधानसभा में भी वह बीजेपी विधायकों के साथ ही नजर आ रहे थे। लगातार भूपेश सरकार पर जुबानी हमला बोल रहे थे। अतत~ रविवार को उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली।

जेसीसीजे से निकालने पर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा था कि पहले क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब मुझ पर कातिलाना हमले होंगे। मेरी हत्या भी कराई जा सकती है। अमित जोगी की नाराजगी इस बात से थी कि गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में वो और बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा क्यों गए थे। अगर कोई बात थी तो उनसे करनी चाहिए थी। इसके पहले करीब 20 दिन पहले ही जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान शर्मा ने कहा था कि अमित जोगी के साथ मेरे विचार नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया।

खबरों से रहें अपडेट
www.scgnews.in
SCG News

मदरसा बोर्ड सहित प्रदेश के मदरसों में किया गया ध्वजारोहण

रायपुर । कार्यालय छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर प्रात: 8:00 बजे ध्वजारोहण किया गया। माननीय अलताफ अहमद , अध्यक्ष छ.ग.मदरसा बोर्ड ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके अलावा छात्र-छात्राओं हेतु सांस्कृतिक-साहित्यिक कार्यक्रमों एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।

कार्यालय छ.ग.मदरसा बोर्ड में प्रात: 8 बजे सचिव डॉ. इम्तियाज अहमद अंसारी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात् सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

प्रदेश के पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में भी ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक-साहित्यिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें मदरसे के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व पर मदरसों में विभिन्न आयोजन किये जाते हैं।

उत्कल बहनें छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने संकल्पित हैं- सावित्री जगत

उत्कल गाड़ा महिला महामंच ने मनाया सावन उत्सव, महिलाओं को सिंगार प्रतियोगिता में किया गया पुरस्कृत

रायपुर। उत्कल गाड़ा महिला महामंच के नेतृत्व में शनिवार को राजधानी रायपुर के नगर निगम गार्डन में सावन उत्सव का आयोजन किया गया जहां समाज की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई और परंपरागत अंदाज में सावन उत्सव मनाया।

छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच सावन के उत्सव और उमंग के साथ हर हर महादेव के जयघोष के साथ पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं का उत्साह सावन उत्सव के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व को परिभाषित करता प्रतीत हुआ।

इस दौरान महिलाओं के बीच सिंगार प्रतियोगिता भी हुई जिसमे परंपरागत अंदाज में सिंगार कर आई महिलाओं को अलग अलग ग्रुप मसलन बेस्ट चूड़ी, बेस्ट साड़ी स्टाइल, बेस्ट मांग टीका, बेस्ट मेकअप, बेस्ट जुड़ा, बेस्ट चोटी, बेस्ट हेयर स्टाइल आदि आदि खिताबों से नवाजते हुए पुरस्कृत भी किया गया। उत्कल गाड़ा महिला महामंच की प्रमुख सावित्री जगत ने सावन उत्सव पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि आज उत्कल गाड़ा महिला मंच ने सावन उत्सव के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव का परिचय दिया।

उत्कल गाड़ा महिला महामंच की बहनों ने छत्तीसगढ़ की समृद्धि की कामना बोलेनाथ से की हम सभी छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने और छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने कृत संकल्पित हैं।

कार्यक्रम में श्रीचंद सुंदरानी संजय श्रीवास्तव गौरी श्रीवास्तव अवस्थी सीमा साहू वंदना मुखर्जी जयंती पर धनिया विभा राव प्रमुख रूप से समाज की महिलाएं सीमा छतरी हेमा सागर पिंकी नेहाल प्रीति सागर बिंदिया नाथ संगीता गौतम मेश्राम संतोषी सोनी माधुरी बघेल आलिम विभाग पद्मिनी निहाल बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग -क्रांति साहू

वोटिंग मशीन से चुनाव न होकर बैलट पेपर से चुनाव हो: नंदकुमार बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में महिला पदाधिकारियों का सम्मेलन किया गया महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक एवं सामाजिक एवं छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक में खेलकूद संगीत में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष चर्चा चली।

कार्यक्रम के संचालक क्रांति साहू ने कहा की जिसमें भारत देश मैं महिलाओं की संख्या लगभग पुरुष के बराबर है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री और राष्टपति को ज्ञापन देकर मांग करने की बात कहीं साथ ही साथ यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार ने महिलाओं को पंचायत चुनाव एवं नगरी निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण छत्तीसगढ़ में है।

इसी तरह से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की आरक्षण होना चाहिए एव छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत ही मेहनत लगन से काम करती हैं जिसको ठान लेती है वह पूरा करके रहती है आज भूपेश बघेल के सरकार ने महिलाओं के लिए गांव-गांव में औद्योगिक पार्क बनाकर महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा अनेको कार्य कर जैसे वह कोदो कुटकी रागी बिस्कुट गोबर से पेंट बनाकर आत्मनिर्भर हो रही है भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीजी माल का प्रारंभ किया है।

इससे महिला सशक्त हो रही है अब महिला 'अबला नहीं सबला है'। कक्षा 10वीं 12वीं कॉलेज या पीएससी या आने को कंपटीशन एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं तो महिलाओं की भागीदारी 60 से 70 प्रतिशत आगे रहती हैं एक महिला शिक्षित हो जाए तो दो परिवार को शिक्षित करती है।

कार्यक्रम के अंत में प्रस्ताव पास किया 1/ महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा में 50प्रतिशत आरक्षण की प्रधानमंत्री राष्टपति से करने की बात यही जिसको सभी कोई ध्वनि पहुंच से ताली बजाकर समर्थन किया और दिल्ली आगामी दिल्ली के जंतर मंतर में इसके लिए धरना आंदोलन की बात की किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नंद कुमार बघेल राष्ट्रीय अध्यक्ष में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष श्रीधर चंद्राकर प्रकोष्ठ अध्यक्ष पुष्पांजलि वर्मा बिलासपुर संभाग अध्यक्ष अन्नपूर्णा ध्रुव बिलासपुर जिला के अध्यक्ष संध्या राव बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अंकिता जायसवाल सचिव मनीषा जायसवाल बिलासपुर बिलासपुर शहर के अध्यक्ष रजनी परिहार विनीता चौहान पूजा वस्त्रकार बिलासपुर शहर जिला अध्यक्ष माही सिंह अंशु पांडेय पवन कुमार यादव दीपक ध्रुव आदि उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेम्बर भवन में ध्वजारोहण किया गया

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर चेम्बर कार्यालय- चै.देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में ध्वजारोहण किया गया।

कार्यक्रम के पूर्व सर्वप्रथम पूजा-अर्चना कर भारत माता एवं राष्टपिता महात्मा गांधी की तस्वीर में माल्यार्पण, गुलाल व पुष्प अर्पित किया गया । पश्चात चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी द्वारा प्रात:ठीक 9.30 बजे ध्वजारोहण किया गया।

ध्वजारोहण के पश्चात राष्टगान एवं भारत माता का जयघोष किया गया एवं सभी पदाधिकारियों,व्यापारी सदस्यों एवं उद्योगपति बंधुओं को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर चेम्बर सलाहकार-अमर गिदवानी, दीपक बल्लेवार, जितेंद्र दोशी, परमानंद जैन (गणेश सायकल), परमानंद जैन (राईस मिल), सुरिन्दर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष- विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, प्रदेश प्रभारी आईटी सेल- कैलाश खेमानी, कार्यालय प्रभारी नरेश गंगवानी, कार्यकारी महामंत्री- कपिल दोशी, पुर्व कोषाध्यक्ष- प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष-हीरा माखीजा, अमृत लाल पटेल,नरेन्द्र हरचंदानी, पृथ्वीपाल सिंह छाबड़ा, मनोज कुमार जैन, भरत जैन, जय नानवानी, संगठन मंत्री- महेंद्र कुमार बगरोडीया, मंत्री- शंकर बजाज, राजेन्द्र खटवानी, राकेश (जनक) वाधवानी, जयराम कुकरेजा, दिलीप इसरानी, विक्रांत राठौर, अमर धिंगानी, प्रदेश सांस्कृतिक प्रभारी- आलोक शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य- सतीश श्रीवास्तव, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल, उपाध्यक्ष-विपुल पटेल, हिमांशु वर्मा, दिलीप पंसारी अध्यक्ष-छत्तीसगढ़ पान व्यापारी संघ, लखमशी पटेल अध्यक्ष-छत्तीसगढ़ टिम्बर व्यापारी संघ, जीवत बजाज अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्लास्टिक निर्माता एवं विक्रेता संघ, लोकेश जैन, सी.ए. मुकेश मोटवानी, परमिंदर खनूजा, नागेंद्र तिवारी, मनोज गुप्ता, पीताम्बर कोडवानी, संजय जयसिंघ, वासु माखीजा, दीपक विधानी, नरेश ठक्कर सहित अनेक व्यापारीगण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

राहुल अग्रवाल (टिंकू)
जिला कोषाध्यक्ष, जिला
कांग्रेस कमेटी सूरजपुर ,
Chairman
PRA.Gruop
surajpur chattisgarh

समस्त
प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
एवं रक्षा बंधन
की हार्दिक
शुभकामनाएं

सरपंच व
समस्त ग्रामवासी
ग्राम भरतपुर
तहसील,सूरजपुर,
जिला सूरजपुर
छत्तीसगढ़,

प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस एवं
रक्षा बंधन
की हार्दिक शुभकामनाएं

राजकुमार सिंह
सरपंच
ग्राम पंचायत करौटी,(ए)
तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर
छत्तीसगढ़।।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा आसमां पब्लिशर्स इंडिया प्रा.लि. जयराम काम्पलेक्स गली, मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979